



इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Steel
Government of India



गतिविधियों का | BRIEF REPORT
संक्षिप्त विवरण | OF ACTIVITIES
2023

SAIL joins the Nations's PRIDE.....!!



Fuel Tankers made of SAIL's material for Chandrayaan Project



विषय-सूची CONTENTS

अनुक्रमणिका / INDEX

विषय/Subject	पृष्ठ सं./ Page No.
इस्पात मंत्रालय: 2023 की क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण / Ministry of Steel : Brief Statement of Activities of 2023	
1.0 इस्पात क्षेत्र में रुझान और विकास	2
2.0 वर्ष 2023 के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहल	8
3.0 सीपीएसई द्वारा प्रमुख विस्तार/परियोजनाएं/संयुक्त उद्यम	13
4.0 वर्ष 2023 के दौरान सीपीएसई की मुख्य विशेषताएं	22
1.0 Trends and developments in steel sector	28
2.0 Major initiatives taken by the Ministry during 2023	33
3.0 Major Expansion/Projects/ Joint Ventures by CPSEs	37
4.0 Highlights of CPSEs during 2023	45

इस्पात मंत्रालय वर्ष 2023 के क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण

1.0 इस्पात क्षेत्र में रुझान और विकास

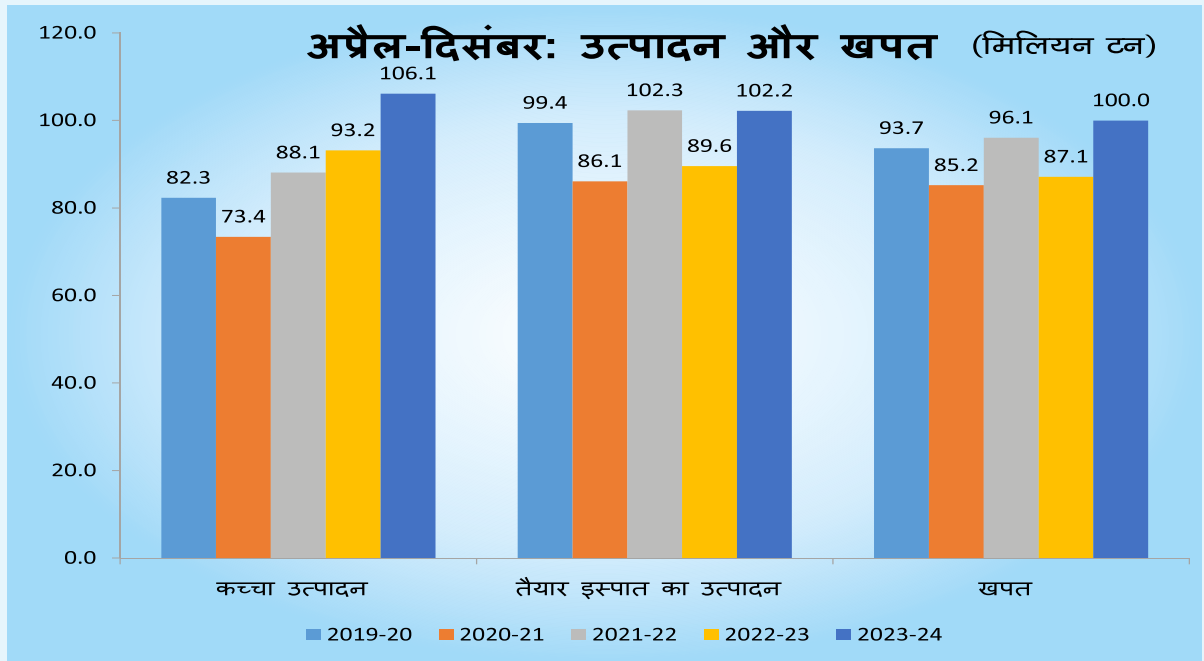
इस्पात क्षेत्र निर्माण, बुनियादी ढांचे, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में, इस्पात क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है।

देश में इस्पात के उत्पादन और खपत दोनों में भारी वृद्धि देखी गई है। प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2013-14 में 59 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 119 किलोग्राम हो गई है। भारत ने वर्ष 2022-23 में 123 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया है और कैलेंडर वर्ष 2018 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इस्पात उत्पादन की क्षमता वर्ष 2012-13 में 97 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 171.35 मिलियन टन हो गई है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा विनिर्माण, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और आवास क्षेत्रों के निर्माण और मेक-इन-इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन आदि जैसी विभिन्न अन्य पहलों पर सरकार के बल और प्रतिबद्धता का परिणाम है। उत्पादन का बड़ा हिस्सा (लगभग 37%) द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में होता है, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने वाले छोटे उत्पादक शामिल हैं।

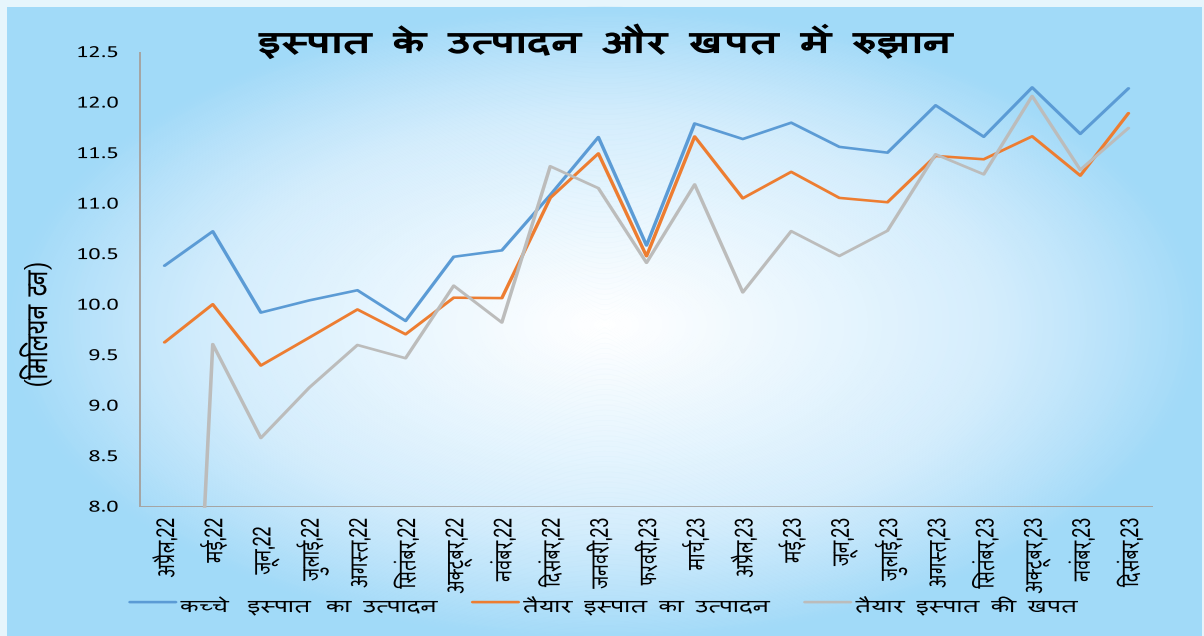
भारतीय इस्पात क्षेत्र: उत्पादन और खपत

वित्तीय वर्ष 2024 के अप्रैल-दिसंबर के दौरान इस्पात क्षेत्र का प्रदर्शन किसी भी वित्तीय वर्ष के अप्रैल-दिसंबर की तुलना में सबसे अच्छा रहा है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के अप्रैल-दिसंबर के दौरान इस्पात का संचयी उत्पादन और खपत निम्नलिखित तालिका और ग्राफ में दिया गया है:

तालिका 2: उत्पादन और खपत (मिलियन टन में) (अप्रैल-दिसंबर)					
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कच्चे इस्पात का उत्पादन	82.298	73.419	88.073	93.158	106.132
तैयार इस्पात उत्पादन	99.421	86.098	102.299	89.555	102.196
खपत	93.659	85.183	96.051	87.136	99.991
स्रोत संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)					

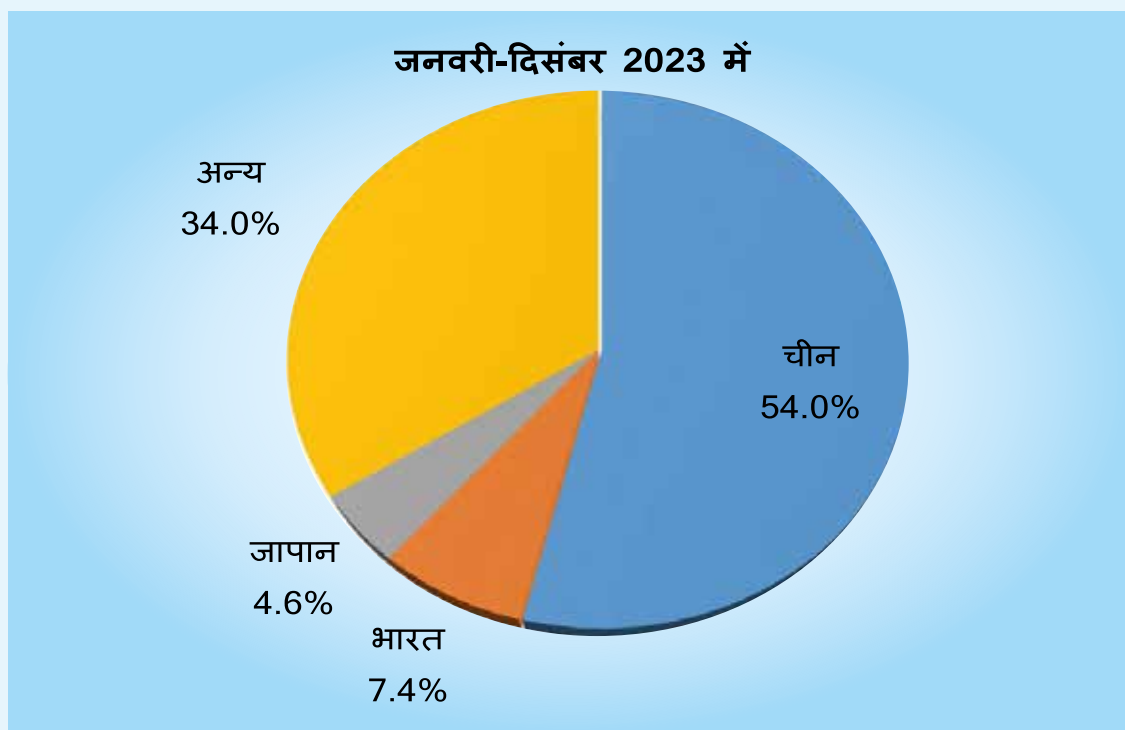


- माह-वार उत्पादन और खपत माह-दर-माह उतार-चढ़ाव का संकेत देती है। मोटे तौर पर कहें तो वर्ष 2020-21 के बाद इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, जिसके दौरान कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन और खपत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। अप्रैल, 2022 से कच्चे इस्पात के उत्पादन, तैयार इस्पात और खपत को नीचे दिए गए ग्राफ से देखा जा सकता है:



- कैलेंडर वर्ष 2023 में कच्चे इस्पात का वैश्विक उत्पादन 0.026% घटकर 1888.20 मिलियन टन हो गया, जो वर्ष 2022 में 1888.70 मिलियन टन था। प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों में, भारत ने विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्ष 2023 में सबसे अधिक वृद्धि हासिल की। भारत वर्तमान में वर्ष 2023 में कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका और ग्राफ से देखा जा सकता है:

तालिका: कच्चे इस्पात का विश्व का प्रमुख उत्पादक (एमटी में)					
अवधि	चीन	भारत	जापान	अन्य	विश्व
2023	1019.10	140.2	87	641.9	1888.20
% शेयर करना	53.97	7.43	4.61	33.0	100.00
% विकास	0.0	11.8	-2.5	-2.0	-0.026
स्रोत: जेपीसी और डब्ल्यूएसए					

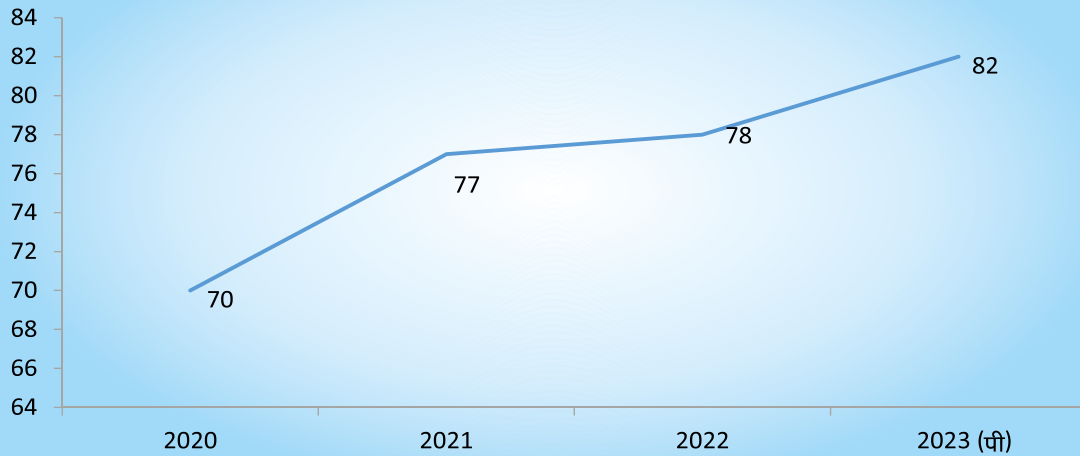


- वर्ष 2023 के दौरान, कच्चे इस्पात उत्पादन में क्षमता उपयोग 82% (अनंतिम) है। सक्रिय नीतियों और सुरक्षा उपायों के कारण, क्षमता उपयोग बढ़ रहा है जबकि हमने कच्चे इस्पात बनाने की पर्याप्त क्षमता जोड़ी है जैसा कि नीचे दी गई तालिका और ग्राफ़ से देखा जा सकता है:

वर्ष	कच्चे इस्पात के उत्पादन में क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)
2020	70
2021	77
2022	78
2023 (अ)	82
अ : अनंतिम, स्रोत: जेपीसी	

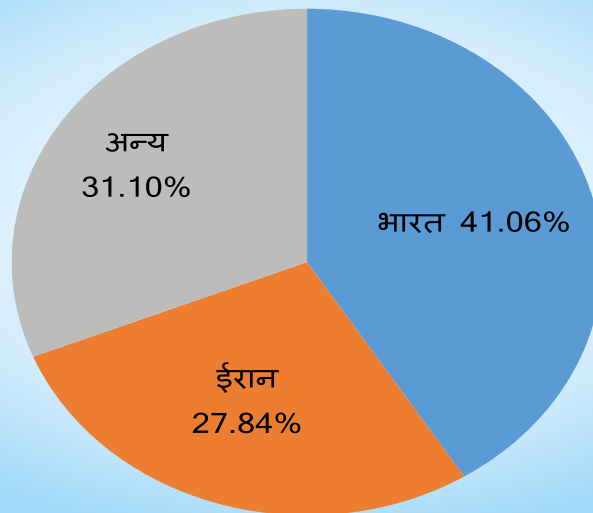


कच्चे इस्पात के उत्पादन में क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)



- भारत वर्तमान में वर्ष 2023 में डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई)/स्पंज आयरन का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो 49.33 मिलियन टन स्पंज आयरन का उत्पादन करता है (वर्ल्ड स्टील द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार)।

2023 में प्रमुख स्पंज आयरन उत्पादक देश



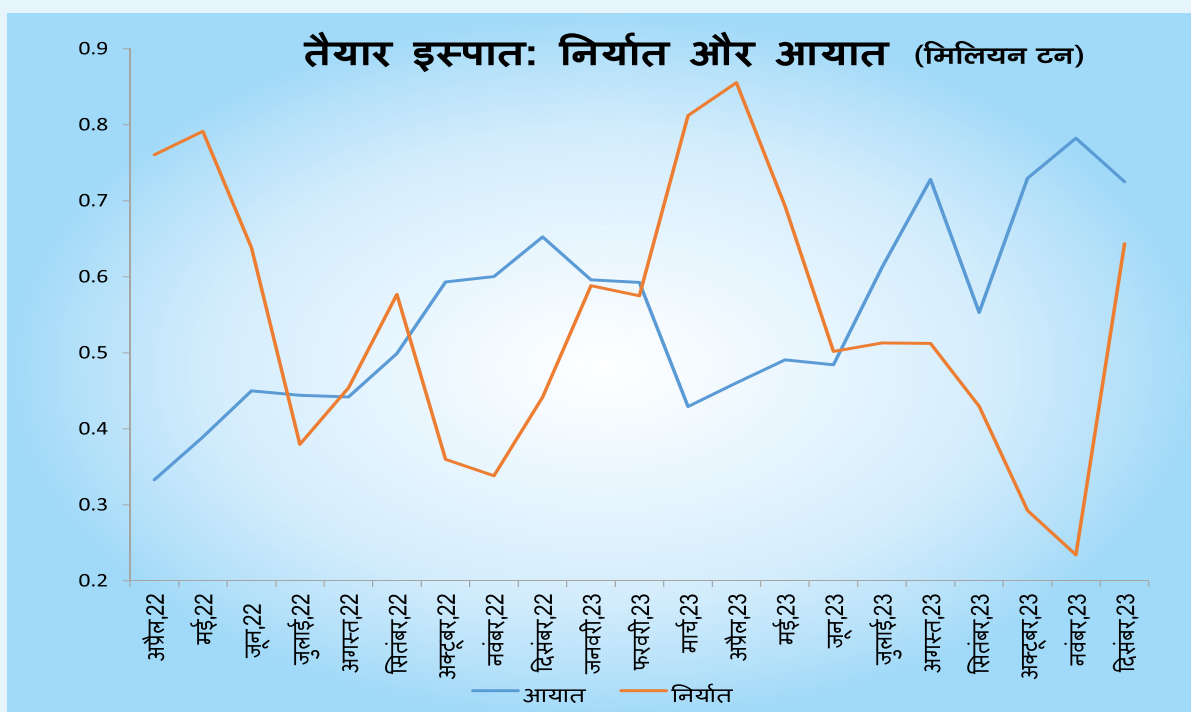
भारतीय इस्पात क्षेत्र: इस्पात का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

- पिछले चार वर्षों के दौरान, भारत प्रत्येक वर्ष कुल तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक था। हालाँकि, चालू वित्तीय वर्ष, अप्रैल-दिसंबर 2023-24 में, भारत तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

तालिका 3: निर्यात और आयात (000 टन)					
	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24 (अप्रैल–दिसंबर)
निर्यात	8355	10784	13494	6716	5565
आयात	6768	4752	4669	6021	4675
शुद्ध निर्यात	1588	6031	8824	695	–891
स्रोत: जेपीसी					

- वर्ष 2023–24 की प्रथम तिमाही में, भारत तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक था। हालाँकि, चालू वित्तीय वर्ष के महीने-वार डेटा से संकेत मिलता है कि जुलाई, 2023 के बाद से भारत ने शुद्ध निर्यातक का दर्जा खो दिया है, जैसा कि नीचे तालिका और ग्राफ़ में देखा जा सकता है:

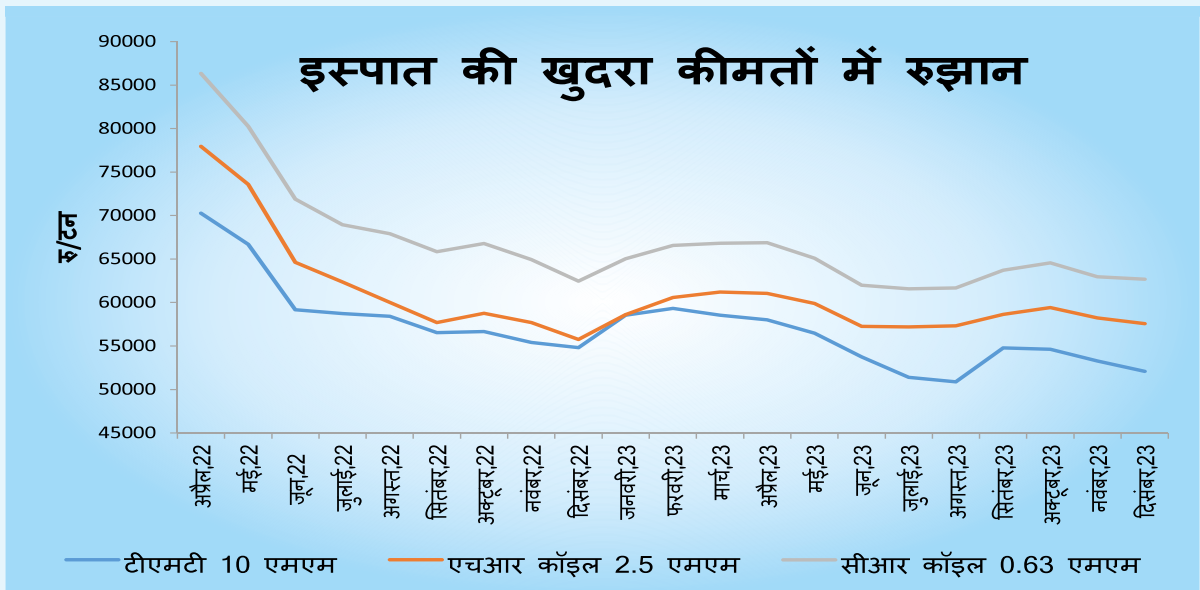
तालिका 4: 000 टन में तैयार इस्पात का माहवार आयात और निर्यात									
वस्तु	अप्रैल 23	मई 23	जून 23	जुलाई 23	अगस्त 23	सितम्बर 23	अक्टूबर 23	नवंबर 23	दिसम्बर 23
आयात	460	491	484	613	728	553	730	782	725
निर्यात	855	693	502	513	512	430	293	234	644
शुद्ध निर्यात	395	202	18	–100	–216	–123	–437	–548	–82
स्रोत: जेपीसी									





भारतीय इस्पात क्षेत्र: इस्पात की कीमतें

- 16.1.1992 को लौह एवं इस्पात का मूल्य विनियमन समाप्त कर दिया गया। तब से घरेलू इस्पात की कीमतें बाजार की शक्तियों के परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित होती हैं।
- घरेलू इस्पात की कीमतें कच्चे माल की कीमतों के रुझान, बाजार में मांग-आपूर्ति की स्थिति, अंतरराष्ट्रीय मूल्य रुझान सहित अन्य से प्रभावित होती हैं।
- रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण मार्च, 22 में इस्पात (टीएमटी, एचआरसी और सीआरसी) की कीमतें चरम पर थीं। उसके बाद वैश्विक और घरेलू दोनों कारकों के कारण इस्पात की कीमतें दिसंबर, 22 तक कम हो गईं। टीएमटी, एचआरसी और सीआरसी की कीमतें चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-दिसंबर) में कम हुई हैं जैसा कि निम्नलिखित ग्राफ में देखा गया है:



अप्रैल, 2023 से लौह अयस्क की कीमतों में महीने-दर-महीने उतार-चढ़ाव देखा गया है, हालांकि नीचे दिए गए ग्राफ से वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा सकती है:



- मई, 2022 में ऐतिहासिक शिखर के बाद एचसीसी कोकिंग कोल एफओबी ऑस्ट्रेलिया की कीमतें जून, 22 के बाद कम हो गई हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, एचसीसी कोकिंग कोयले की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है, जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ से देखा जा सकता है:



2.0 वर्ष 2023 के दौरान मंत्रालय की प्रमुख पहलों की उपलब्धियां

विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना

जुलाई, 2021 में, सरकार ने इस्पात क्षेत्र में पूंजी निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजित करने और प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देकर देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6322 करोड़ रु. के 5 साल के वित्तीय परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी थी। योजना 29.7.2021 को अधिसूचित की गई थी और विस्तृत योजना दिशानिर्देश 20.10.2021 को प्रकाशित किए गए थे। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023–24 (पीएलआई वित्तीय वर्ष 2024–25 में जारी की जाएगी) से शुरू होती है।

17.03.2023 को इस्पात मंत्रालय ने 57 आवेदनों वाली 27 चयनित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह योजना 24780 हजार टन की क्षमता वृद्धि के साथ 29,530 करोड़ रुपये की कुल निवेश प्रतिबद्धता को आकर्षित करेगी।

इस्पात निर्माण का हरित विकासीकरण

इस्पात क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस्पात का उत्पादन एक कार्बन-सघन प्रक्रिया होने के कारण वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में इस्पात क्षेत्र एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है। जैसे-जैसे दुनिया जलवायु परिवर्तन से निपटना चाहती है, इस्पात उद्योग से उत्सर्जन कम करना एक प्रमुख प्राथमिकता बन गई है। भारत, दुनिया के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक के



रूप में, इस्पात की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए अपने इस्पात क्षेत्र का विकारबनीकरण करने में एक अनूठी चुनौती का सामना कर रहा है। हालाँकि, निवल शून्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, जैसा कि सीओपी-26 में बताया गया है, इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र के विकारबनीकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र के विकारबनीकरण के विभिन्न स्तरों पर चर्चा, विचार-विमर्श और सिफारिश करने के लिए उद्योग, शिक्षा जगत, थिंक टैंक, एस एंड टी निकायों, विभिन्न मंत्रालयों और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ 14 कार्य बलों का गठन किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने और उपयोग के संवर्धन के लिए एक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। मिशन में इस्पात क्षेत्र को भी हितधारक बनाया गया है। इस्पात क्षेत्र ने आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं में विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों (बीएटी) को अपनाया है।

सरकारी बजट के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास

इस्पात मंत्रालय "लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना" नामक अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लौह एवं इस्पात क्षेत्र के सामने आने वाले जलवायु परिवर्तन (हरित इस्पात उत्पादन, एच2 आधारित इस्पात उत्पादन, सीसीयूएस आदि) अपशिष्ट उपयोग, संसाधन दक्षता आदि जैसे ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिए नई वैकल्पिक प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने हेतु प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और इस्पात कंपनियों से संयुक्त सहयोगात्मक मोड में अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत वित्त पोषण के लिए विचार किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों के लिए समन्वय और वित्तीय योगदान दोनों के संदर्भ में औद्योगिक भागीदारी अनिवार्य है।

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, सरकारी बजट से 239.63 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 360.48 लाख रुपये की कुल लागत वाली कुल 4 आर एंड डी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में इस्पात मंत्रालय की 14 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं चल रही हैं।

इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश

इस्पात मंत्रालय ने इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पेश किया है, जिसके माध्यम से उद्योग, उपयोगकर्ताओं और जनता को बड़े पैमाने पर गुणवत्ता वाले इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू और आयात दोनों माध्यमों से घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम उपयोगकर्ताओं को केवल प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाला इस्पात ही उपलब्ध कराया जाए।

आज तक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत कार्बन इस्पात, मिश्र धातु इस्पात और स्टेनलेस इस्पात को शामिल करते हुए 145 भारतीय मानकों को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, इस्पात से बने सामान और वस्तुएं जैसे स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब, ट्रांसफार्मर के लेमिनेशन/कोर, टिन प्लेट और टिन

मुक्त इस्पात के उत्पादों आदि को भी इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की धोखाधड़ी को रोकने के लिए अधिसूचित किया गया है।

लौह एवं इस्पात क्षेत्र में सुरक्षा: लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार करना

किसी भी उद्योग के कामकाज में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न केवल अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए बल्कि पर्यावरण और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। लौह और इस्पात उत्पादन एक जटिल और खतरनाक गतिविधि है, इसलिए चोटों और दुर्घटनाओं को रोकने, स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

हितधारकों, शिक्षाविदों आदि के साथ व्यापक परामर्श के बाद, लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए 25 सामान्य न्यूनतम सुरक्षा दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार किया गया था। ये सुरक्षा दिशानिर्देश वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं और लौह एवं इस्पात उद्योग में सुरक्षा पर आईएलओ अभ्यास संहिता (कोड ऑफ प्रैक्टिस) की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। “सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सिद्धांत और परिभाषाएँ” पर विश्व इस्पात संघ के मार्गदर्शन दस्तावेज़ से भी इनपुट लिया गया है। ये दिशानिर्देश इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों का एक पुस्तक “लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश” के रूप में माननीय इस्पात मंत्री द्वारा 17 फरवरी, 2020 को लोकार्पण किया गया।

भारतीय इस्पात उद्योग और उसके संघों के हितधारकों से कार्यबल के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु इन दिशानिर्देशों को पूरे दिल से अपनाने का आग्रह किया गया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से लौह एवं इस्पात उद्योग द्वारा सुरक्षा दिशानिर्देशों को अनिवार्य रूप से अपनाए जाने को सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि यह व्यवसाय सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (ओएसएचएंडडब्ल्यूसी) संहिता 2020 की धारा 18 के तहत मानक तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार

राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार (नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड) 2022 लौह और इस्पात क्षेत्र में धातुकर्मियों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार पांच श्रेणियों में दिया जाता है: लाइफटाइम अचीवमेंट, नेशनल मेटलर्जिस्ट, यंग मेटलर्जिस्ट (पर्यावरण), यंग मेटलर्जिस्ट (मेटल साइंस), तथा लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)। पुरस्कार समारोह 22 नवंबर, 2023 को आयोजित किया गया और विजेता थे:

- डॉ. कामाची मुदाली उथंडी – लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड
- डॉ. देबाशीष भट्टाचार्य – नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड
- डॉ. रामेश्वर शाह – लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास
- डॉ. निलोय कुंडू – यंग मेटलर्जिस्ट (पर्यावरण) अवार्ड
- एगिलन मुथुमनिकम – यंग मेटलर्जिस्ट (धातु विज्ञान) अवार्ड



इस पुरस्कार का उद्देश्य विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और भविष्य के ऊर्जा स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए धातु विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। यह पुरस्कार घरेलू इस्पात उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के विजन का भी समर्थन करता है।

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ इस्पात मंत्रालय का जुड़ाव

इस्पात मंत्रालय ने इस्पात उत्पादन सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए 2000 से अधिक इस्पात इकाइयों के जियोलोकेशन को अपलोड करते हुए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में बीआईएसएजी-एन की क्षमताओं को एकीकृत किया है। यह जानकारी रेलवे लाइन विस्तार, अंतर्देशीय जलमार्ग, राजमार्ग, बंदरगाह और गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी की योजना बनाने में सहायता करेगी। मंत्रालय ने लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क खदानों और लौह अयस्क स्लरी पाइपलाइनों के डेटा को भी मैप किया है, जिससे महत्वपूर्ण कच्चे माल के स्रोतों की बेहतर दृश्यता और प्रबंधन संभव हो सकता है। मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे की 22 प्रमुख कमियों की पहचान की है जिनका व्यापक और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अन्य मंत्रालयों के सहयोग से समाधान करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इस्पात मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान में सीपीएसई सदस्यों को शामिल किया है।

इस्पात मंत्रालय को वर्ष 2022 की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अनुरूप कुशल लॉजिस्टिक्स (एसपीईएल) के लिए क्षेत्रीय योजनाएं बनाने का आदेश दिया गया है। एसपीईएल को एक व्यापक पद्धति का उपयोग करके विकसित किया गया था, जिसमें अंतर्देशीय जलमार्ग योजना, राष्ट्रीय रेलवे योजना, मसौदा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स योजना और हितधारकों के इनपुट सहित विभिन्न स्रोतों से जानकारी शामिल थी। इसका उद्देश्य जालना और रायपुर जैसे महत्वपूर्ण इस्पात समूहों की अनूठी आवश्यकताओं और चिंताओं को समझना था। कुशल लॉजिस्टिक्स योजना (एसपीईएल) के लिए प्रारंभिक मसौदा क्षेत्रीय योजना को प्रमुख इस्पात उत्पादकों और संघों के बीच प्रसारित किया गया था और एक अच्छी तरह से सूचित रणनीति सुनिश्चित करते हुए इसे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया था। हितधारकों से प्राप्त सुझावों की जांच की जा रही है और अंतिम एसपीईएल डीपीआईआईटी के माध्यम से ईजीओएस को प्रस्तुत किया जाएगा।

इस्पात स्क्रेप पुनर्चक्रण नीति

इस्पात स्क्रेप पुनर्चक्रण नीति (एसएसआरपी) को वर्ष 2019 में अधिसूचित किया गया है। यह समयावधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न लौह स्क्रेप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए देश में धातु स्क्रेपिंग केंद्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। एसएसआरपी प्रदूषण में कटौती और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए संगठित, सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ तरीके से संग्रह, विखंडन और टुकड़े-टुकड़े करने की गतिविधियों के लिए एक मॉडल तैयार करता है। विखंडन केंद्र और स्क्रेप प्रसंस्करण केंद्र की जिम्मेदारियां, एग्रीगेटर्स की भूमिकाएं और सरकार, निर्माता और मालिक की जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। पुनर्चक्रण द्वारा उत्पादित कटे हुए स्क्रेप का उपयोग इस्पात बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाएगा। इससे इस्पात बनाने के लिए स्क्रेप की आयात निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और इस्पात के उत्पादन की लागत भी कम होने की संभावना है। इस दिशा में, इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सीपीएसई एमएसटीसी

लिमिटेड ने महिंद्रा एक्सेलो के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) में महिंद्रा एमएसटीसी रीसाइविंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएमआरपीएल) की स्थापना की है। अब तक, संयुक्त उद्यम ने ग्रेटर नोएडा (एनसीआर), चेन्नई, पुणे, इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में आठ (8) वाहन स्क्रेपिंग केंद्रों स्थापित किए हैं। एमएसटीसी को कंपनी द्वारा विकसित पोर्टल पर 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों की नीलामी करने का भी काम सौंपा गया है। मंत्रालय ईएलवी पुनर्चक्रण प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ कार्य कर रहा है।

इस्पात मंत्रालय के तहत सीपीएसई द्वारा कैपेक्स

भारत में उच्च और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इस्पात अवसंरचना निर्माण में पूंजीगत व्यय के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। इस्पात सीपीएसई अपनी कैपेक्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) का उपयोग कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, इस्पात सीपीएसई का लक्ष्य 11,590.46 करोड़ रु. (आरई) था जिसके मुकाबले सीपीएसई ने 10,525.84 करोड़ रुपये का कैपेक्स हासिल किया। वित्त वर्ष 2022–23 में कैपेक्स पिछले पांच वर्षों में इस्पात सीपीएसई द्वारा हासिल किया गया सबसे अधिक कैपेक्स था।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कैपेक्स लक्ष्य 10,300.85 करोड़ रु. (बीई) था। इस बीई लक्ष्य के मुकाबले, इस्पात सीपीएसई ने दिसंबर, 2023 तक 6290.66 करोड़ रुपये (61.1%) का कैपेक्स हासिल किया है। कैपेक्स प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और सीपीएसई को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने तथा भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

वर्ष 2023–24 (दिसंबर, 23 तक) के दौरान सीपीएसई द्वारा शुरू की गई प्रशिक्षण और कौशल विकास गतिविधियाँ

वर्ष 2023–24 (दिसंबर, 23 तक) के दौरान, 5091 उम्मीदवारों ने सीपीएसई के माध्यम से प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अलावा, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) प्रशिक्षण के भाग के रूप में, सीपीएसई ने 1357 अपने कर्मचारियों, 4460 संविदा श्रमिकों और 366 स्थानीय युवाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया है।

इस्पात मंत्रालय के तहत सीपीएसई में शिक्षुता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण:-



पीएसयू	वित्त वर्ष 2023-24 (दिसम्बर, 23 तक) में प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उम्मीदवार		रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) प्रशिक्षण (वित्त वर्ष 2023-24 दिसंबर, 23 तक)		
	आरडीएटी/बीओएटी द्वारा प्रदान किए गए स्लॉट	2023 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	स्वयं के कर्मचारी	संविदा श्रमिक	स्थानीय युवा
केआईओसीएल	185	132	492	1979	366
मेकॉन	33	33	145	—	—
मॉयल (नवंबर 23 तक)	430	330	373	—	—
आरआईएनएल	1019	1019	—	—	—
सेल	4239	2989	84	2481	—
एमएसटीसी	—	14	263	—	—
एनएमडीसी	618	574*	—	—	—
कुल	6524	5091	1357	4460	366

* एनएमडीसी लिमिटेड ने चार वर्षों की अवधि में कुल 1600 कर्मचारियों के लिए रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग (आरपीएल) प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए एनएसडीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएसडीसी को कुल राशि का 50% भुगतान किया गया है और एनएसडीसी ने संयुक्त रूप से आरपीएल प्रशिक्षण देने के लिए पहले ही एक प्रशिक्षण भागीदार खोज लिया है। एनएसडीसी को नौकरी संबंधी कार्य दिए गए हैं। सभी परियोजनाओं में प्रशिक्षण शीघ्र ही शुरू होगा।

3.0 सीपीएसई द्वारा प्रमुख विस्तार/परियोजनाएं/संयुक्त उद्यम

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल के विभिन्न संयंत्रों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 5,100 करोड़ रुपये की कई वृद्धि, परिवर्धन, प्रतिस्थापन योजनाएं (एएमआर) कार्यान्वयनाधीन थीं, जिनमें से प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं:

- पॉलीक्लोरीनेटेड बाईफिनायल के पर्यावरणानुकूल प्रबंधन हेतु स्टेटिक इकाई की स्थापना, सिंटर प्लांट-II हेतु मल्टीसाइक्लोन के प्रतिस्थापन के रूप में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसीपीटेटर्स की स्थापना और भिलाई इस्पात संयंत्र में कोक ओवन बैटरी सं 7 और 8 का पुनः निर्माण।
- ब्लास्ट फर्नेस सं.4 में चौथे स्टोव की स्थापना, व्हील एवं एक्स्ल संयंत्र में एनडीटी सुविधाओं की स्थापना, नए 1250 टीपीडी बीओओ आक्सीजन संयंत्र हेतु ऊर्जा वृद्धि योजना और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में नए गैस फायर्ड बॉयलर की स्थापना।
- एनएसपीसीएल से एमएसडीएसआईवी तक 220 केवी में ऊर्जा निकासी, कोक हैंडलिंग और गैस हैंडलिंग सुविधाओं के संवर्धन के साथ कोक ओवन बैटरी सं. 2 का पुनः निर्माण, जेडएलडी अवधारणा के साथ सीओ और सीसीडी के प्रवाह शोधन संयंत्र का उन्नयन, एसएमएस-II में लेडल फर्नेस के साथ चौथे स्लैब कास्टर की स्थापना तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र में जेडएलडी के कार्यान्वयन हेतु शोधन प्रणाली-1 की स्थापना।

- नया सिंटर संयंत्र, कोक ओवन बैटरी सं. 8 का पुनर्निर्माण, बीएसएल व टाउनशिप के लिए दामोदर नदी से अपरिष्कृत जल को लाने हेतु विकल्पी प्रणाली का विकास, एसडब्ल्यूएस (स्टील वर्क स्टेशन) में मौजूदा आरआरआई (रुट रिले इंटरलॉकिंग) प्रणाली को एसएसआई (सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग) प्रणाली से प्रतिस्थापन, प्रस्तावित 2000 टीपीडी ऑक्सीजन हेतु ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था, बीओओ आधार पर 2000 टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना, एचएसएम की स्वचालित प्रणाली का उन्नयन, डीवीसी के सीटीपीएस से एमआरएस के बीच 22 केवी तीसरी लाइन की स्थापना और बोकारो इस्पात संयंत्र के टर्बो ब्लोअर सं. 5 हेतु टर्बाइन और सहायक सुविधाओं का प्रतिस्थापन

उपरोक्त में से, 500 करोड़ रुपये की निम्नलिखित परियोजनाएं वर्ष 2022-23 के दौरान पूरी कर ली गई हैं :

- बीएसपी में पॉलीक्लोरीनेटेड बाईफिनायल्स के पर्यावरणानुकूल प्रबंधन हेतु स्टैटिक इकाई की स्थापना ।
- बीएसपी में सिंटर संयंत्र- II हेतु मल्टी-साईक्लोन के प्रतिस्थापन के रूप में इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रीसीपीटेटर्स की स्थापना ।
- आरएसपी में एनएसपीसीएल से एसएसडीएस- IV तक 200 केवी में ऊर्जा निकासी ।
- आरएसपी में जेडएलडी अवधारणा के साथ सीओ और सीसीडी के प्रवाह शोधन संयंत्र का उन्नयन ।
- बीएसएल में कोक ओवन बैटरी – 8 का पुनः निर्माण ।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयंत्रों नामतः भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र में प्रमुख वृद्धि, परिवर्धन, प्रतिस्थापन योजनाएं (एएमआर) (150 करोड़ रु. व अधिक की लागत वाली) परियोजनाएं शुरू / कार्यान्वित होने वाली हैं जिसके लिए कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान आदेश दे दिए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

- कनवर्टर वेसल्स, टूनियन रिंग्स, सपोर्ट सिस्टम की प्रतिस्थापना और भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित एसएमएस-II में तीन कनवर्टरों हेतु द्वितीयक उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना
- बोकारो इस्पात संयंत्र में ब्लास्ट फर्नेस-3 के पुराने सब-सिस्टम का सुधार
- बोकारो इस्पात संयंत्र में कोक ओवन बैटरी सं. 6 का पुनः निर्माण
- दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कोक ओवन बैटरी 4 (सीओबी-4) का पुनः निर्माण

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए बीओओ/एमडीओ/सीओएम आधार पर ऑर्डर दे दिए गए हैं :

- राउरकेला इस्पात संयंत्र में सीओएम आधार पर 1000 टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना
- तसरा खदानों में एमडीओ की सहभागिता
- दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में बीओओ आधार पर 1250 टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

1. वायु पृथक्करण संयंत्र-बीओओ

- संयंत्र-1 और संयंत्र-2 को जून, 23 में चालू किया गया, जिससे ब्लास्ट फर्नेस-3 को पूरी क्षमता से फिर से शुरू करने और संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया। पीजी टेस्ट-1 दिसंबर, 23 में पूरा हुआ। फिलहाल दोनों संयंत्र चालू हैं।

2. आरआईएनएल फोर्ज्ड व्हील संयंत्र

- आयात प्रतिस्थापन के लिए भारतीय रेलवे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लालगंज, उत्तर प्रदेश स्थित फोर्ज्ड व्हील संयंत्र, जिसकी प्रति वर्ष एक लाख पहिये उत्पादन करने की क्षमता है।
- सफल समापन के बाद 31.03.2023 को प्रारंभिक स्वीकृति प्रमाणपत्र (पीएसी) जारी किया गया।
- उत्पादन में धीरे-धीरे सुधार हुआ और रेलवे को अप्रैल, 23 में 1039 पहिये के स्तर से दिसंबर, 23 में 3128 से पहिये तक भेजे गए।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसंबर, 23 तक भारतीय रेलवे को कुल 17721 पहिये (एलएचबी + एलओसीओ) भेजे गए।

एनएमडीसी लिमिटेड:

एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) की स्थापना:

- एनएमडीसी स्टील लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 2 जनवरी, 2015 को निगमित एक सार्वजनिक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी/ओ एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट, नगरनार, बस्तर, छत्तीसगढ़ में है।
- यह 3 एमटीपीए क्षमता का ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर से 16 कि.मी. दूर स्थित नगरनार में स्थापित किया गया है। एनआईएसपी के निर्माण का निर्णय लौह अयस्क भंडार के साथ जुड़े होने और निवेश योग्य अधिशेष की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।
- संयंत्र 24 अगस्त, 2023 को कार्यात्मक हो गया था जब पहला कॉइल रोल आऊट किया गया था। पहला एचआर कॉइल 24.08.2023 को रोल आऊट किया गया। परियोजना की लागत 23840 करोड़ रुपये है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) को 3 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था।
- दिनांक 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार, एनएसएल ने ब्लास्ट फर्नेस से लगभग 5.33 लाख टन हॉट मेटल, 2.10 लाख टन तरलीकृत इस्पात, 1.95 लाख टन एचआर कॉइल का उत्पादन किया है।

एनएमडीसी की अन्य ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाएं

1. नगरनार, छत्तीसगढ़ में 3.0 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र

- क्षमता— 3.0 एमटीपीए ।
- परियोजना लागत: 23840 करोड़ रुपये ।
- ब्लास्ट फर्नेस का संचालन 12.08.2023 को शुरू हुआ और हॉट मेटल का उत्पादन 15.08.2023 को किया गया ।
- एसएमएस ऑपरेशन 21.08.2023 को शुरू हुआ ।
- टीएससी—एचएसएम प्रचालन 24.08.2023 को शुरू हुआ और पहला एचआर कॉइल 24.08.2023 को शुरू हुआ ।
- भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा नगरनार में एनएमडीसी इस्पात संयंत्र दिनांक 03.09.2023 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था ।

2. छत्तीसगढ़ में स्लरी पाइपलाइन परियोजना चरण—1

- एनएमडीसी ने स्लरी पाइपलाइन परियोजना का निर्माण शुरू किया है जिसमें नगरनार में 2.0 एमटीपीए पेलेट संयंत्र, बचेली में 2.0 एमटीपीए अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र और बचेली से नगरनार तक 135 किलोमीटर स्लरी पाइपलाइन तथा छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी सहायक प्रणालियाँ शामिल हैं । स्लरी पाइपलाइन लेयिंग पैकेज, स्लरी पंप हाउस पैकेज, नगरनार में पेलेट प्लांट का प्रौद्योगिकी पैकेज, मुख्य सबस्टेशन पैकेज और बचेली में अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र के प्रौद्योगिकी पैकेज जैसे सभी पैकेज प्रदान किए गए हैं और साइट पर काम प्रगति पर है । सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई हैं ।
- परियोजना लागत: 2907 करोड़ रुपये ।
- परियोजना की समग्र प्रगति: 55.10% ।
- पानी की पाइपलाइन और स्लरी पाइपलाइन का 49 किमी संचयी निचलाकरण पूरा हुआ ।

3. स्क्रीनिंग प्लांट—III, किरंदुल, छत्तीसगढ़

- एनएमडीसी ने किरंदुल कॉम्प्लेक्स, बैलाडिला, छत्तीसगढ़ में 12.0 एमटीपीए स्क्रीनिंग प्लांट —III की स्थापना शुरू की है । सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई हैं । ड्राई सर्किट पैकेज, वेट सर्किट पैकेज, आरडब्ल्यूएलएस पैकेज, मुख्य सबस्टेशन पैकेज जैसे प्रमुख पैकेज प्रदान किए गए हैं और साइट पर काम प्रगति पर है ।
- परियोजना लागत: 2719 करोड़ रुपये ।
- परियोजना की समग्र प्रगति: 48.46% ।



4. **मौजूदा स्क्रीनिंग प्लांट में 5वीं स्क्रीनिंग लाइन का निर्माण और भंडार-5, बचेली कॉम्प्लेक्स, बैलाडिला, छत्तीसगढ़ में डाउनहिल कन्वेयर सिस्टम का उन्नयन**
 - परियोजना लागत: 67 करोड़ रुपये।
 - परियोजना की समग्र प्रगति: 90%।
 - स्क्रीनिंग प्लांट में 5वीं स्क्रीनिंग लाइन पूरी हो गई है और परिचालन में ले ली गई है।
5. **डोनिमलाई कॉम्प्लेक्स, कर्नाटक में 7.0 एमटीपीए स्क्रीनिंग और बेनेफिशियेशन संयंत्र-॥ की स्थापना।**
 - परियोजना लागत: 1044 करोड़ रुपये।
 - अपेक्षित समापन: मार्च, 26।
 - वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी जैसी वैधानिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।
 - निविदा संबंधी कार्यकलाप प्रगति पर हैं।
6. **भंडार 14 और 11सी पर नया क्रशिंग प्लांट और डाउनहिल कन्वेयर सिस्टम**
 - परियोजना लागत: 1756 करोड़ रुपये।
 - पर्यावरण मंजूरी प्रगति पर है।
 - निविदा संबंधी गतिविधियां प्रगति पर हैं।
 - समापन अवधि: पैकेज देने के बाद कार्य निष्पादन हेतु 36 महीने (पर्यावरण मंजूरी से सम्बद्ध)।
7. **किरंदुल से जगदलपुर तक किरंदुल-कोट्टावलसा लाइन का दोहरीकरण (लगभग 150 किमी)**
 - परियोजना को एनएमडीसी द्वारा वित्त पोषित, जमा आधार पर पूर्वी तट रेलवे द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक 150 कि.मी. दोहरीकरण में से कुल 106 कि.मी. का कार्य चालू हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। स्वीकृत 1500 करोड़ रुपये (अधिकतम), की राशि में से एनएमडीसी ने अब तक 1363 करोड़ रुपये जारी किए और शेष 137 करोड़ रुपये कार्य प्रगति के आधार पर चरणों में जारी किए जाएंगे।
8. **एनएमडीसी की सौर परियोजनाएं: बचेली कॉम्प्लेक्स, छत्तीसगढ़ में रूफटॉप सौर संयंत्र**
 - क्षमता: 425 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र।
 - परियोजना लागत: 10 वर्षों के लिए प्रचालन एवं रख रखाव (ओ एंड एम) सहित 3.36 करोड़ रुपये।
 - परियोजना 14.03.2023 को चालू हुई।

मॉयल लिमिटेड

1. छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन:

दिनांक 16 जनवरी, 2023 को मॉयल और सीएमडीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, सीएमडीसी ने सरकार को गवेषण हेतु एमसीआर 2016 के नियम 67 के तहत एक उपयुक्त ब्लॉक के आरक्षण के लिए आवेदन किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 04.10.2023 को गवेषण हेतु बलरामपुर जिले का 218 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आवंटित किया। मॉयल जल्द ही इस क्षेत्र में गवेषण कार्य शुरू करेगा।

2. टेक्समिन के साथ समझौता ज्ञापन:

भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम), धनबाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत अंतर-विषयक साइबर-फिजिकल स्टेम (एनएमआईसीपीएस) के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत "खनन और गवेषण के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र की स्थापना की है, जिसे टेक्समिन के रूप में जाना जाता है। मॉयल लिमिटेड और टेक्समिन ने खनन परियोजनाओं में खनिज गवेषण, मशीनीकरण, डिजिटलीकरण आदि क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास के लिए सहयोगी अनुसंधान दल के रूप में एक साथ काम करने के लिए दिनांक 17.12.2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मेकॉन लिमिटेड

1. **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:** मेकॉन, इस्पात मंत्रालय (एमओएस) की परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में, मंत्रालय की प्रमुख उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को कार्यान्वित कर रही है। योजना के तहत, 30,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 25 एमटीपीए की अपेक्षित क्षमता निर्माण विशेष इस्पात में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। इस योजना के लिए 27 कंपनियों ने 10730 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ इस्पात मंत्रालय के साथ 57 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

2. **सबसे लंबी एचडीडी क्रॉसिंग:** मेकॉन, माननीय प्रधान मंत्री की ऊर्जा गंगा की दूरदर्शी परियोजना के निष्पादन के लिए पीएमसी सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के माध्यम से विभिन्न राज्यों में घरों में पाइप से खाना पकाने की गैस प्रदान करना है। मेकॉन ने 24 राज्यों में 4800 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइन पूरी कर ली है और 5000 किलोमीटर पाइपलाइन परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

गुवाहाटी में आईजीजीएल की नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड परियोजना (एनईजीजी) इस प्रतिष्ठित परियोजना का हिस्सा है, जिसमें मेकॉन ने परियोजना (एनईजीजी) के लिए परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श (पीएमसी) सेवाएं प्रदान करते हुए अप्रैल, 2023 में ब्रह्मपुत्र नदी पर (असम में जोरहाट से माजुली तक) 4080 मीटर की देश की सबसे लंबी हॉरिजेंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग (एचडीडी) क्रॉसिंग पूरी की है।

मेकॉन एकमात्र स्वदेशी डिजाइन, इंजीनियरिंग और पीएमसी संगठन है, जिसके पास एचडीडी द्वारा लंबी (~4000 मीटर) रिवर क्रॉसिंग निष्पादित करने का अनुभव है।



3. **फ्लोटिंग जेट्टी और डीजल/पेट्रोल नावों को सीएनजी में बदलने की परियोजनाएं:** मेसर्स गेल द्वारा मेकॉन को खिरकियाघाट (जिसे अब नमोघाट के नाम से जाना जाता है) में गंगा नदी पर अपनी तरह के पहले फ्लोटिंग जेट्टी (माइल्स स्टील माड्यूलर जेट्टी पर) पर सीएनजी डिस्पेंसिंग स्टेशन और 700 से अधिक डीजल/पेट्रोल नौकाओं को सीएनजी में बदलने के लिए इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (ईपीएमसी) सेवाएं सौंपी गई हैं। इन परियोजनाओं का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वाराणसी में किया गया। इस स्टेशन को मलेशिया के कुआला लम्पुर में तेल और गैस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नवाचार से सम्मानित किया गया है।

इस परियोजना के तहत मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट (एमआरयू) अवधारणा के आधार पर दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी डॉक्टर बूस्टर स्टेशन (डीबीएस) संत रविदास घाट पर गंगा फेरी लाइन के दूसरे छोर पर स्थापित किया गया था और माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।

ये परियोजनाएं गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक कदम हैं और इनसे प्रदूषण कम होने और समुद्री जीवन को बचाने की उम्मीद है।

4. **ब्लास्ट फर्नेस का चालू होना:** मेकॉन, बीएफ कॉम्प्लेक्स की अवधारणा से लेकर चालू होने तक की पूरी जानकारी और प्रौद्योगिकी प्रदान करता है और यह एक मात्र स्वदेशी कंपनी है जिसके पास अपना स्वयं का ब्लास्ट फर्नेस डिजाइन है जिसे देश भर में 23 छोटे इस्पात संयंत्रों में स्थापित किया गया है और द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में 7 से 8 एमटी योगदान देता है।

मेकॉन ने बंगाल एनर्जी, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में अपना स्वयं का डिजाइन किया हुआ 0.4 एमटीपीए ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। ब्लास्ट फर्नेस सभी आधुनिक सुविधाओं जैसे स्टेक्स, बेल लेस टॉप (बीएलटी), पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई), फिल्टर बेड स्लैग ग्रेनुलेशन प्लांट (एसजीपी) आदि से सुसज्जित है।

5. **बोकारो इस्पात संयंत्र के सीओबी#8 को चालू करना:** मेकॉन, कोक ओवन बैटरियों की अवधारणा से लेकर चालू होने तक की पूरी जानकारी और प्रौद्योगिकी प्रदान करता है और यह एकमात्र स्वदेशी कंपनी है जिसके पास अपनी 7एम ऊँची कोक ओवन बैटरी डिजाइन है।

सीओबी#8, बीएसएल मेकॉन द्वारा चालू की गई 33वीं बैटरी है। सीओबी#8 ने लगातार परिचालन मापदंडों को पूरा किया है, और चालू होने की तारीख से केवल 2-3 महीनों के भीतर 94-96 पुशिंग (अधिकतम रेटेड 100 पुशिंग संख्या में से) हासिल की है। उत्पादन मापदंडों को पूरा करने के लिए जब भी आवश्यकता हो पुशिंग की संख्या को 100 तक बढ़ाया जा सकता है। प्रदूषण के मामले में इसका प्रदर्शन लगभग शून्य रिसाव रहा है।

सीओबी#8 को फाइबर-रीइन्फोर्स्ड सीमेंटिशियस मैट्रिक्स (एफआरसीएम) पद्धति (भारत में पहली बार किसी कोक ओवन बैटरी में उपयोग किया गया) का उपयोग करके मौजूदा कंक्रीट नोजल डेक की मरम्मत के साथ चालू किया गया था।

6. **रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट का उद्घाटन:** माननीय प्रधान मंत्री ने विशाखापत्तनम में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया। यह संयंत्र समैरियम-कोबाल्ट

और नियोजिमियम-आयरन-बोरॉन जैसे दुर्लभ पृथ्वी चुंबक का उत्पादन करेगा। इस सुविधा के साथ, भारत दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक बनाने की क्षमता वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा।

मेकॉन विशाखापत्तनम में संयंत्र की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, पर्यवेक्षण, निर्माण और कमीशनिंग गतिविधियों में शामिल था।

7. **एनएसएल की शुरुआत:** एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) को मेगा मॉड्यूल प्रौद्योगिकीय सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है जिसमें 4506 एम3 (उपयोगी मात्रा) क्षमता के साथ भारत में सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस में से एक ब्लास्ट फर्नेस, थिन स्लैब कास्टर (टीएससी) के साथ हॉट स्ट्रिप मिल, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) और दो 7 मीटर ऊँचे कोक ओवन शामिल हैं।

मेकॉन, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) के 3 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए परामर्श तथा परियोजना निगरानी और निर्माण पर्यवेक्षण व प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) सेवाएं प्रदान कर रहा है।

8. **पेटेंट प्रदान करना:** मेकॉन को कुल 50 पेटेंट प्रदान किये गये हैं। हाल ही में:

- “बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस वेसल सस्पेंशन सिस्टम” के नए डिजाइन के आविष्कार के लिए पेटेंट।
- मेकॉन को ‘नॉन-डिस्पर्सिव इंफ्रा-रेड (एनडीआईआर) विधि का उपयोग कर सतत मल्टी कंपोनेंट गैस एनालाइज़र’ के आविष्कार के लिए एक पेटेंट प्रदान किया गया है। विकसित प्रणाली गैसीय प्रदूषकों सीओ, सीओ₂, एनओएक्स (एनओ, एनओ₂), एसओ₂ की सांद्रता के मापन के लिए उपयोगी है।

9. **रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट:** नवीकरणीय ऊर्जा विकास परियोजनाओं के तहत, मेकॉन ने मेकॉन मुख्यालय, रांची में 4 चरणों में 140 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है। 80 केडब्ल्यूपी क्षमता वाला सौर संयंत्र पहले ही 3 चरणों में स्थापित किया जा चुका है और सफलतापूर्वक चल रहा है।

मार्च, 22 में, चौथे चरण में 60 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, इसके साथ मेकॉन मुख्यालय में कुल सौर स्थापित क्षमता अब 140 केडब्ल्यूपी है। सौर संयंत्र ग्रिड से जुड़ा है और यह सालाना लगभग 80,000 केडब्ल्यूएच ऊर्जा उत्पन्न करेगा।

केआईओसीएल लिमिटेड

1. **देवदारी खान में खनन प्रचालन का विकास और प्रारंभ**

कर्नाटक सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 17क (2) के तहत लौह और मैंगनीज अयस्क के खनन के लिए केआईओसीएल के पक्ष में देवदारी रेंज, संदूर तालुक, बल्लारी जिले में 470.40 हेक्टेयर लौह अयस्क ब्लॉक के आरक्षण हेतु दिनांक 23.01.2017 को राजपत्र अधिसूचना को जारी किया। केआईओसीएल ने लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क (2023 का एमएल संख्या 020) के लिए 50 वर्षों की अवधि हेतु 388 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए दिनांक 02.01.2023 को निदेशक, खान और भूविज्ञान, कर्नाटक सरकार के साथ देवदारी लौह अयस्क खदान का खनन पट्टा विलेख निष्पादित किया और उप-पंजीयक



संदूर तालुक, जिला बल्लारी के कार्यालय में दिनांक 18.01.2023 को देवदारी लौह अयस्क खदान का खनन पट्टा विलेख भी पंजीकृत किया।

कर्नाटक सरकार ने वन भूमि के डायवर्जन के लिए दिनांक 11.04.2023 को सरकारी आदेश जारी किया। डीसीएफ बल्लारी ने दिनांक 03.01.2024 के मेल माध्यम से समझौते के निष्पादन के लिए वन पट्टा समझौते का मसौदा साझा किया।

मेकॉन ने दिनांक 31.08.2023 को संशोधित खान योजना प्रस्तुत की थी। खदान योजना को आईबीएम अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.10.2023 को अनुमोदित किया गया था।

केआईओसीएल ने अक्टूबर, 2024 से देवदारी लौह अयस्क खान से लौह अयस्क का खनन शुरू करने की योजना बनाई।

2. केआईओसीएल लिमिटेड, मंगलुरु पैलेट संयंत्र इकाई में वर्टिकल प्रेशर फिल्टर की स्थापना

पैलेट संयंत्र में मौजूदा वैक्यूम डिस्क फिल्टर उच्च एल्यूमिना युक्त और स्लाइमी प्रकृति वाले लौह अयस्क को संभालने में सक्षम नहीं हैं। 04 वर्टिकल प्रेशर फिल्टर, कन्वेयर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रुमेंटेशन उपकरणों सहित सभी सहायक उपकरण स्थापित किए गए हैं। मैसर्स मेट्सो, स्वीडन इंजीनियर्स प्रेशर फिल्टरों को चालू करने के लिए साइट पर कार्य कर रहे हैं। पैलेट फीड के लिए केक के डिस्चार्ज के साथ प्रेशर फिल्टर की एक लाइन की एकीकृत कमीशनिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है।

3. कोक ओवन संयंत्र की स्थापना और कमीशनिंग (मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस का बैकवर्ड इंटीग्रेशन परियोजना)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27.02.2020 के पत्र के माध्यम से, मंगलुरु में ब्लास्ट फर्नेस यूनिट के मौजूदा परिसर के भीतर कोजन कैप्टिव पावर संयंत्र (10 मेगावाट) और डक्टाइल आयरन स्पन पाइप (डीआईएसपी) (0.2 एमटीपीए) के साथ नॉन-रिकवरी कोक ओवन संयंत्र (0.18 एमटीपीए) की स्थापना के लिए पर्यावरण मंजूरी दी थी। केआईओसीएल ने मुख्य पैकेजों के लिए वैश्विक निविदाएं और घरेलू निविदाएं जारी की हैं। कोक ओवन संयंत्र निर्माणाधीन है और दिनांक 30.06.2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

4. केआईओसीएल लिमिटेड, मंगलुरु में आधुनिकीकरण और उन्नयन परियोजनाएं

क) पैलेट संयंत्र इकाई में कोक शेड और मशीनीकृत सामग्री हैंडलिंग सिस्टम

अब तक आरसीसी पाइल और पाइल कैप के कुल 180 नग पूरे हो चुके हैं। आरसीसी रिटेंनिंग वॉल का लगभग 80% तक निर्माण पूरा हो गया है और संरचनात्मक निर्माण कार्य और स्तंभों का निर्माण प्रगति पर है। पाइलिंग और सिविल कार्यों, इस्पात संरचनाओं के निर्माण और निर्माण के लिए परियोजना पूरा होने का कार्यक्रम दिनांक 31 अप्रैल, 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। कन्वेयर, वे फीडर, उपकरणों की स्थापना और विद्युत वितरण प्रणाली की अधिप्राप्ति के लिए निविदाएं की गई हैं, जो मूल्यांकन के अधीन हैं। पीपीयू में मशीनीकृत सामग्री हैंडलिंग प्रणाली कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 31.12.2024 तक पूरी हो जाएगी।

ख) पैलेट संयंत्र की इंड्यूरेंटिंग मशीन के लिए एलएनजी डुअल फायर बर्नर सिस्टम की स्थापना

विस्तृत इंजीनियरिंग के लिए मैसर्स ईआईएल को वर्क ऑर्डर दिया गया था और मैसर्स ईआईएल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, बर्नर प्रबंधन प्रणाली की आपूर्ति के लिए दिनांक 02.09.2023 को निविदा जारी की गई थी। निविदा दिनांक 14.12.2023 को खोली गई थी। निविदा के लिए प्राप्त हुई एकमात्र बोली तकनीकी मूल्यांकन के अधीन है। यदि एजेंसी बाजार मूल्य जानने के लिए प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक रूप से योग्य है तो एकमात्र बोली की मूल्य बोली खोली जाएगी। चूंकि देवदारी लौह अयस्क खदान परियोजना पर पहले ही अधिक पूंजीगत व्यय किया जा चुका है अतः एलएनजी दोहरी बर्नर प्रणाली परियोजना का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2024-25 में किया जाएगा।

4.0 वर्ष 2023 के दौरान सीपीएसई की मुख्य उपलब्धियां

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

1. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उत्पादन संबंधी प्रगति

- अब तक का सबसे अधिक वार्षिक हॉट मेटल उत्पादन, 19.409 मिलियन टन
- अब तक का सबसे अधिक क्रूड इस्पात उत्पादन, 18.2921 मिलियन टन
- अब तक का सबसे अधिक क्रूड इस्पात उत्पादन, 17.246 मिलियन टन
- अब तक का सबसे अधिक वार्षिक लौह अयस्क उत्पादन, 34.15 मिलियन टन

2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के 9 माह के दौरान उत्पादन संबंधी प्रगति

इकाई : '000टी

संयंत्र/मर्दे	अप्रैल-दिसंबर, 23		सीपीएलवाई में % वृद्धि
	2023-24	2022-23	
हॉट मेटल	15153	14160	7
क्रूड इस्पात	14223	13337	7
बिक्री योग्य इस्पात	13718	12547	9

3. वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही (एच1) वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही

'रुपए करोड़ में

विवरण	पहली छमाही (एच1) 2023-24	पहली छमाही (एच1) 2022-23	सीपीएलवाई में % वृद्धि
कुल आय	54687	51022	7.18
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	1898	523	262.90
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	1390	391	255.49



4. चालू वर्ष 2023 के दौरान बिक्री संबंधी प्रगति और पहल:

- i) चालू वर्ष 2023 में सीएमओ की बिक्री 16.72 मिलियन टन थी जो विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5% अधिक है।
- ii) चालू वर्ष 2023 के दौरान भारतीय रेलवे को कुल 11.59 लाख टन रेल की आपूर्ति की गई, कुल रेल आपूर्ति में 260 मीटर लंबी-रेल वेल्डेड-पैनल घटक लगभग 86% शामिल है, जो अब तक की सबसे अधिक आपूर्ति है।
- iii) आर 350 एचटी ग्रेड में हेड हार्डेड रेल्स का एक रेल भारतीय रेलवे को भेजा गया है।
- iv) सेल ने भारतीय नौसेना के जहाजों एंड्रोथ, अंजादीप संशोधक, विंध्यगिरि, महेंद्रगिरि और अमिनी के लिए समग्र प्लेटों की आपूर्ति की।
- v) डिजिटलीकरण की दिशा में, ग्राहकों और आगंतुकों के लिए आसान नेविगेशन और सूचना पहुंच की सुविधा के लिए एआई आधारित चैटबॉट 'सेल सारथी' पेश किया गया है। सीएमओ ने व्हाट्सएप पर वेरिफाइड बिजनेस अकाउंट खोला है। व्हाट्सएप अकाउंट सेल सारथी ऐप के साथ एकीकृत है।
- vi) मूल्य वर्धित उत्पादों के साथ विशिष्ट क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाने और नए बाजारों का पता लगाने के लिए सेल लगातार नए ग्रेड जैसे आरएसपी में एचएसएम 2 से सेलफॉर्मिंग 410, बीएसएल में एचडीजीएल से 0.35 मिमी जीएसएम 80 जीपी, एचएसएफक्यू 550 का उत्पादन कर रहा है। आरएसपी में एचएसएम 2 से एपीआई ग्रेड और हाय स्ट्रेंथ एलपीजी (आईएस 15914 एचएस 345) एचआरसी के लिए प्रमाणन प्राप्त किया गया था। आईएसपी में 15बी25, 10बी33, 1030सीआर, 19एमएनबी4 (संशोधित हाई सी), मूल्य वर्धित सेमिस: आईएसपी में एसयूपी 11ए, 51सीआरवी4, 20एमएनसीआर5, इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। सेल ने भारतीय रेलवे की आवश्यकतानुसार आर-350 एचटी ग्रेड में हेड हार्डेड रेल्स को सफलतापूर्वक विकसित किया है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- ब्लास्ट फर्नेस -3 को 701 दिनों के बाद दिनांक 30.12.2023 को प्रज्ज्वलित किया गया।
- विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों जैसे हॉट मेटल -3.403 एमटी (10%), क्रूड इस्पात- 3.22 एमटी (11%), और विशेष इस्पात-2.771 एमटी (11%) में वृद्धि हासिल की गई।
- विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13% की वृद्धि के साथ 3.084 एमटी का बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन हासिल किया।
- विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 21% की वृद्धि के साथ 3.07 एमटी की बिक्री मात्रा प्राप्त की गई।
- विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8% की वृद्धि के साथ 16,766 करोड़ रुपये का बिक्री कारोबार किया गया।

- विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 47% की वृद्धि के साथ 9.91 लाख टन मूल्य वर्धित इस्पात की बिक्री प्राप्त की गई।

लागत में कमी और राजस्व अधिकतमकरण हेतु उत्पादन मद में निम्नलिखित पहल शामिल हैं:

- बिक्री योग्य इस्पात में उच्च अंत मूल्य वर्धित इस्पात का अधिकतमीकरण अप्रैल-दिसंबर वर्ष 2023-24 में बढ़कर 42% हो गया, जो वर्ष 2022-23 में 26% के स्तर पर था।
- आयरन फाइन को प्रतिस्थापित करने के लिए, अप्रैल-दिसंबर, 23 के दौरान सिंटर बनाने में लौह अयस्क स्लाइम के उपयोग में 25% तक सुधार हुआ है

कच्चे माल/कार्यशील पूंजी सहायता को सुरक्षित करने के लिए पहल:

- आयातित कोकिंग कोयले के लिए एक व्यापार भागीदार के माध्यम से \$100 मिलियन की क्रेडिट लाइन स्थापित की जा सकती है
- ब्लास्ट फर्नेस-3 के लिए कच्चे माल/कार्यशील पूंजी सहायता हेतु ब्लूम्स की 90,000 टन प्रति माह की आपूर्ति के लिए एक ग्राहक के साथ समझौता ज्ञापन (लगभग 800 से 900 करोड़ रुपये की मासिक सहायता) किया गया।

जैम (जीइएम) अधिप्राप्ति

- चालू वित्त वर्ष में दिसंबर, 23 तक की गई कुल 1922.5 करोड़ रुपये की मूल्य अधिप्राप्ति के कारण विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 54.34% के सुधार को दर्ज किया गया।

पुरस्कार

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगातार 5 वीं बार **राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार** के रूप में आरआईएनएल को ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और जीएचजी (ग्रीनहाउस गैस) में कमी की दिशा में किये गए प्रयासों के सम्मान स्वरूप, सीआईआई गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा 2017 से लगातार सातवीं बार **उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार** से सम्मानित किया गया।

एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी का वास्तविक निष्पादन

विवरण	(एमटी में)
वर्ष 2023-24 (दिसंबर' 2023 तक) के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन	31.79 एमटी
वर्ष 2023-24 (दिसंबर' 2023 तक) के दौरान लौह अयस्क की घरेलू बिक्री	31.79 एमटी
वर्ष 2023-24 (दिसंबर' 2023 तक) के दौरान लौह अयस्क की निर्यात बिक्री	शून्य
वर्ष 2023-24 (दिसंबर' 2023 तक) के दौरान लौह अयस्क की कुल बिक्री	31.79 एमटी
वर्ष 2023-24 (सितंबर' 2023 तक) के दौरान एनएमडीसी ने 3,608 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ अर्जित किया	



अन्य उपलब्धियां

कौशल विकास

एनएमडीसी ने स्थानीय बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से शैक्षिक संस्थाओं की सुविधाओं वाले केंद्र **"एजुकेशन सिटी"** जिसमें एक ही परिसर में प्राथमिक से लेकर व्यावसायिक संस्थाएं हैं, गीदम, दंतेवाड़ा में स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भागीदारी की है। एनएमडीसी ने वहां स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज का संचालन जारी रखा है, जिसमें दो पाठ्यक्रम (स्ट्रीम्स) अर्थात इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 126 छात्रों को प्रवेश देकर, सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।

एनएमडीसी ने दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन में सहायता करते हुए तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के उद्देश्य को बढ़ावा देना जारी रखा है:

- भांसी में 5 ट्रेडों के साथ आईटीआई को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक वर्ष 128 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।
- नगरनार में वेल्डर और मेसन ट्रेडों के साथ आईटीआई, जिसमें प्रत्येक वर्ष 28 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

खेलों को बढ़ावा : एनएमडीसी ने कर्नाटक के धारवाड़ में कार्य पहल अर्थात् निर्माणाधीन बहुउद्देशीय खेल परिसर में अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण संबंधी कार्य शुरू किया है। कंपनी उपर्युक्त कार्यकलाप में राज्य प्राधिकरणों के साथ भागीदारी कर रही है, जिसमें एनएमडीसी का अंशदान 14.23 करोड़ रुपये तक होगा।

सामग्री प्रबंधन की उपलब्धियां:

I) अधिप्राप्ति:

- 1) इस्पात मंत्रालय द्वारा निर्धारित **840 करोड़** रुपये के लक्ष्य की तुलना में जीईएम पोर्टल के माध्यम से **880 करोड़** रुपये वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति।
- 2) समझौता ज्ञापन द्वारा निर्धारित **25%** के लक्ष्य की तुलना में एमएसई फर्मों के माध्यम से **46%** अधिप्राप्ति।

II) डिजिटल संबंधी पहल:

- 1) **आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन (एसआरएम)** ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल लागू किया गया। जो किसी भी सेवा प्रदाता पर भरोसा किए बिना आंतरिक ई-निविदा गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगा।
- 2) **फाइल लाइफसाइकिल मैनेजमेंट (एफएलएम) (कागज मुक्त कार्यालय)** को हमारे ईआरपी मॉड्यूल में विकसित किया गया है और यह कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।
- 3) टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से एमएसई फर्मों के माल और सेवाओं के चालान की स्वीकृति/अस्वीकृति।

- 4) एसएपी प्रणाली के साथ जीईएम पोर्टल का एकीकरण।
- 5) विक्रेता इनवॉइस प्रबंधन (वीआईएम) पोर्टल का विकास और वीआईएम पोर्टल के साथ टीआरईडीएस पोर्टल का एकीकरण।

मॉयल लिमिटेड

- **उत्पादन:** मॉयल ने दिसंबर, 2023 तक 12.73 लाख मीट्रिक टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन दर्ज किया है, जिसमें विगत वर्ष की समान अवधि (सीपीएलवाई) की तुलना में ~42% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **बिक्री:** 11.01 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री, जो विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में ~40% अधिक थी।
- **इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी):** ईएमडी का उत्पादन भी विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 30% अर्थात् 808 मीट्रिक टन से बढ़कर 1051 मीट्रिक टन हो गया है।
- **फेरो मैंगनीज (एफईएमएन):** एफईएमएन का उत्पादन भी विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में ~6% बढ़ गया है अर्थात् 7363 एमटी से बढ़कर 7831 एमटी हो गया।
- **बिक्री करोबार** भी विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग ~13% बढ़ा, अर्थात् 915.65 करोड़ रु. से बढ़कर 1034.52 करोड़ रु. हो गया।
- **कैपेक्स:** मॉयल ने विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 55% की वृद्धि दर्ज करते हुए 216.09 करोड़ रु. का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) किया है।
- **गर्वमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के माध्यम से अधिप्राप्ति:** मॉयल ने 175 करोड़ रु. के लक्ष्य की तुलना में 282 करोड़ रु. की उच्चतम जीईएम (गर्वमेंट ई-मार्केट प्लेस) की अधिप्राप्ति की है।

मेकॉन लिमिटेड

- मेकॉन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (31 दिसंबर, 2023 तक) में (-) 114.74 करोड़ रु. (अनंतिम) का कर पूर्व लाभ और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक 866.64 करोड़ रु. की ऑर्डर बुकिंग हासिल की है।
- मेकॉन एक ऋण-मुक्त सीपीएसई है, जिसकी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 31 दिसंबर, 2023 तक 40.14 करोड़ रु. और नेटवर्थ 336.46 करोड़ रु. (अनंतिम) है।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में 9.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी विगत वर्ष की तुलना में परिचालन शुद्ध खरीद से राजस्व में लगभग 4.13% की वृद्धि हासिल करने में सफल रहा। पीबीटी लगभग 42.46% बढ़ा। पीएटी में 19.56% वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप



कंपनी की अब तक का सबसे अधिक लाभ हुआ है। वित्तीय वर्ष के दौरान एमएसटीसी की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- एमएसटीसी अपने मार्केटिंग और ई-कॉमर्स वर्टिकल के माध्यम से लेन-देन किए गए सामानों के मूल्य के संदर्भ में 3015.90 बिलियन भारतीय रुपये को पार कर गया है, जो वर्ष 2021-22 में ट्रेड किए गए सामानों के मूल्य से 120% अधिक है;
- कंपनी ने 498.00 करोड़ रुपये की कुल मात्रा दर्ज की है; कंपनी का कुल ई-कॉमर्स सर्विस चार्ज 264.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 288.00 करोड़ रुपये हो गया है, जो 9% की वृद्धि दर्शाता है;
- वित्तीय वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ पिछले वित्तीय वर्ष में 200.05 करोड़ रुपये की तुलना में 239.23 करोड़ रुपये था और वित्तीय वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ पिछले वित्तीय वर्ष के 220.04 करोड़ रुपये की तुलना में 313.48 करोड़ रुपये था, जो मुख्य रूप से ई-कॉमर्स योगदान पर आधारित था;
- प्रति शेयर ₹11.80 का अंतरिम लाभांश दिया। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने 3.20 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की भी सिफारिश की है, जिसका भुगतान शेयरधारकों को आगामी एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद किया जाएगा।
- एमएसटीसी ने केंद्र और राज्य सरकार के लिए 'उपयोगिता अवधि समाप्त' वाहनों के निपटान के लिए ईएलवी पोर्टल लॉन्च किया है।

केआईओसीएल लिमिटेड (वित्त वर्ष 2023-24 के दिसंबर, 2023 तक)

- 1.501 मिलियन टन लौह अयस्क पेलेट्स का उत्पादन हासिल किया गया।
 - 1.469 मिलियन टन लौह अयस्क पेलेट्स की बिक्री।
 - 1481.98 करोड़ रुपए का कारोबार।
 - अप्रैल, 2023 से दिसंबर, 2023 तक 1277.42 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित की।
- (टिप्पणी वित्तीय आंकड़े अनंतिम हैं और लेखापरीक्षा के अधीन हैं।)

MINISTRY OF STEEL BRIEF STATEMENT OF ACTIVITIES OF 2023

1.0 TRENDS AND DEVELOPMENTS IN STEEL SECTOR

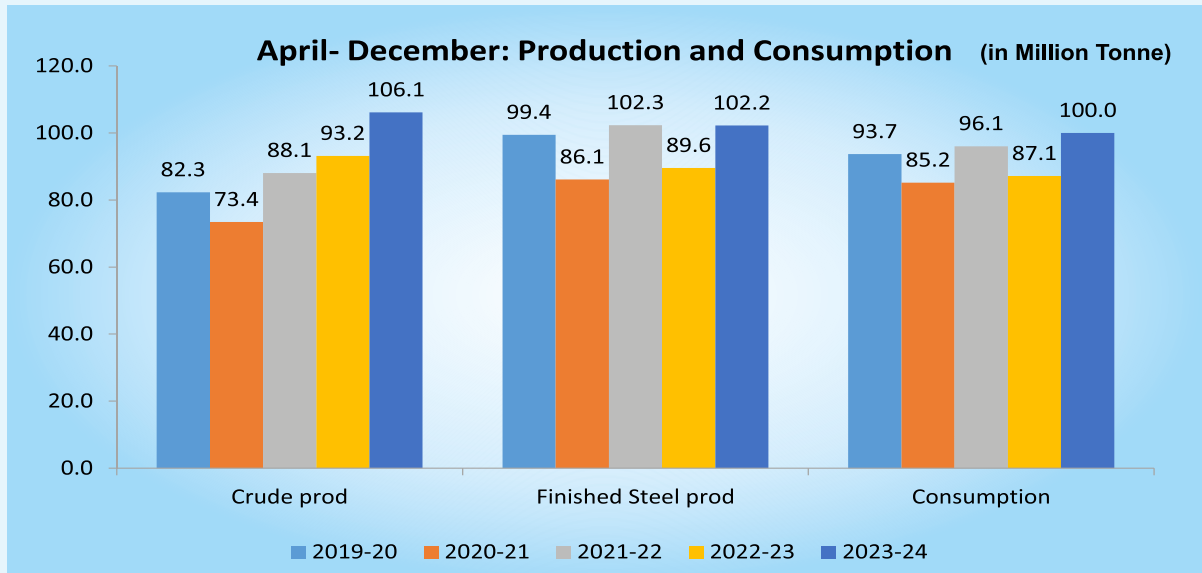
The steel sector plays a pivotal role in crucial sectors such as construction, infrastructure, automobile, engineering and defence. Over the years, the steel sector has witnessed a tremendous growth.

The country has seen a huge growth in both production and consumption of steel. The per capita consumption has risen from 59 kgs in 2013- 14 to 119 kgs in 2022-23. India has produced 123 Million Tonnes of steel in 2022-23 and has become the second largest producer in the world by the calendar year 2018. The capacity of steel production has increased from 97 Million Tonnes in 2012-13 to 171.35 Million Tonnes in 2023-24 which is result of the Government's emphasis and commitment to boosting economic growth and promoting manufacturing especially building infrastructure and housing sectors and various other initiatives like Make-in-India, Smart City Mission, etc. A large share (approx.. 37 %) of the production is contributed by the secondary steel sector comprising of small producers spread across the country employing a large number of people directly or indirectly.

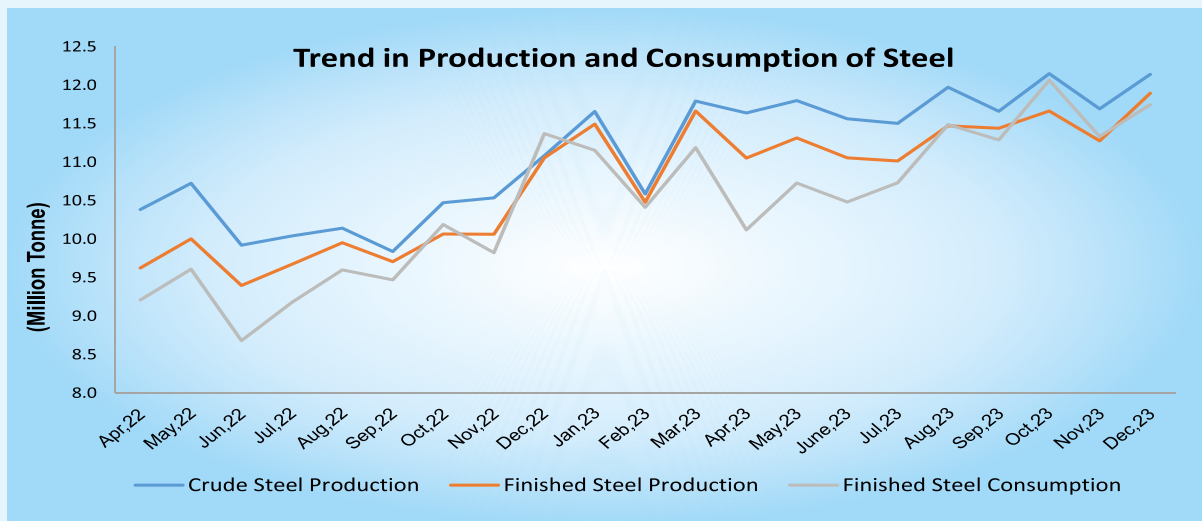
Indian Steel Sector: Production and Consumption

Performance of Steel Sector during April-December, FY'24 has been best ever in April-December of any fiscal year. Cumulative production and consumption of steel during April-December of last five financial years are given in the following table and graph below:

Table 2: Production and consumption (in Million Tonnes) (April- December)					
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Crude Steel production	82.298	73.419	88.073	93.158	106.132
Finished Steel production	99.421	86.098	102.299	89.555	102.196
Consumption	93.659	85.183	96.051	87.136	99.991
Source: Joint Plant Committee(JPC)					



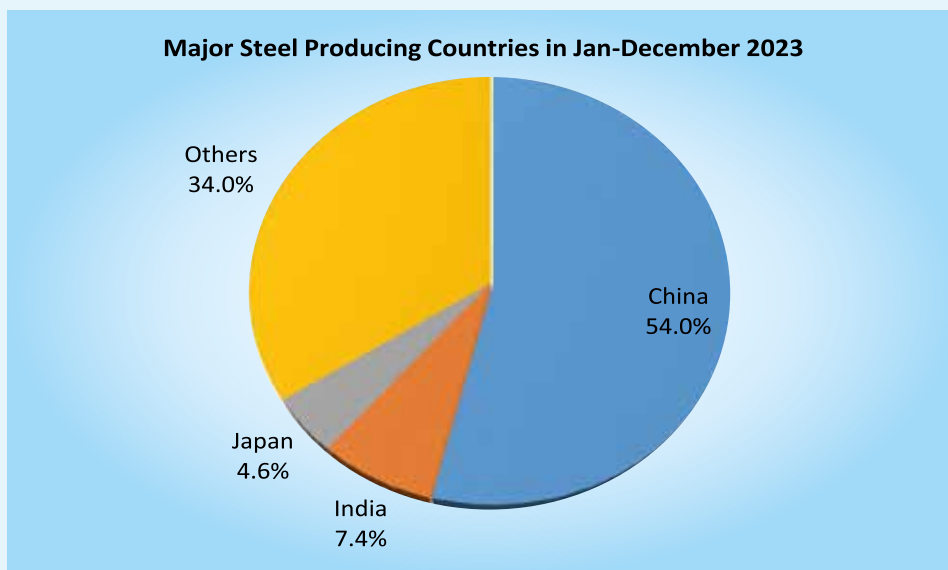
- The month-wise production and consumption indicates month-on-month fluctuations. Broadly speaking it has shown an increasing trend after 2020-21, during which production and consumption was adversely affected by Covid-19 pandemic. The production of crude Steel, finished steel and consumption since April, 2022 may be seen from Graph Below:



- The global production of crude steel declined by 0.026% to 1888.20 MT in Calendar Year 2023 against 1888.70 MT in Year 2022. Among the major steel producing countries, India achieved highest growth in Year 2023 over CPLY. India is currently the world's 2nd largest producer of crude steel in Year 2023 as may be seen from the table and graph below:

Table: World Major Producer of Crude Steel (In MT)					
Period	China	India	Japan	Others	World
2023	1019.10	140.2	87	641.9	1888.20
% Share	53.97	7.43	4.61	33.0	100.00
% Growth	0.0	11.8	-2.5	-2.0	-0.026

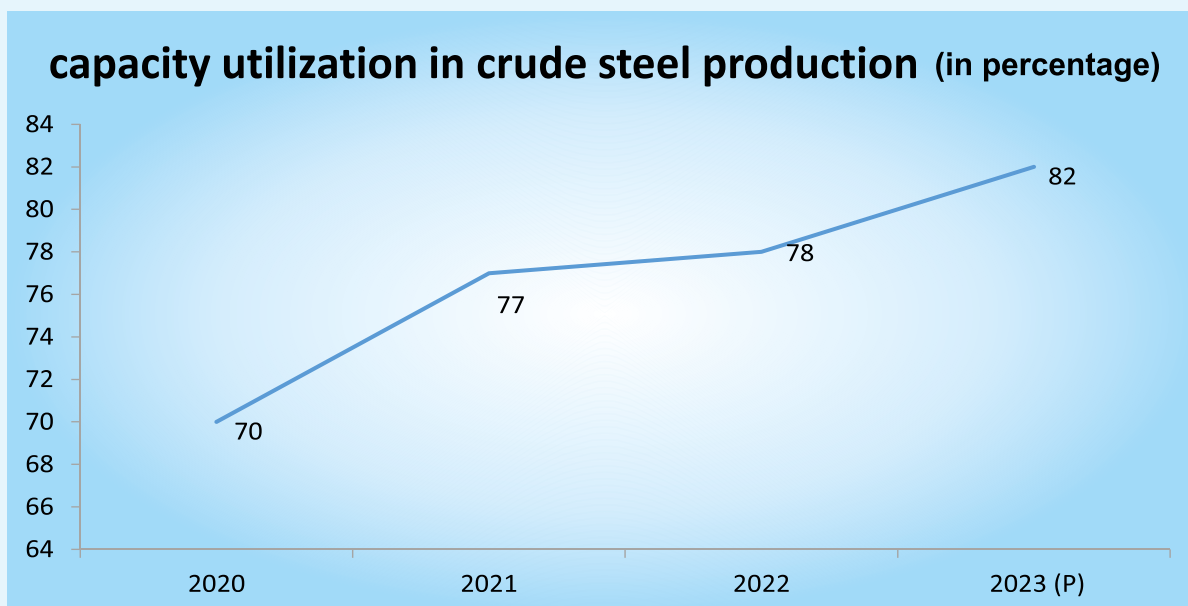
Source: JPC & WSA



- During Year 2023, capacity utilization in crude steel production is 82% (Provisional). Due to proactive policies and safeguard measures, capacity utilization is increasing while we have added substantial crude steel making capacity as may be seen from table and graph below:

Year	capacity utilization in crude steel production (in percentage)
2020	70
2021	77
2022	78
2023 (P)	82

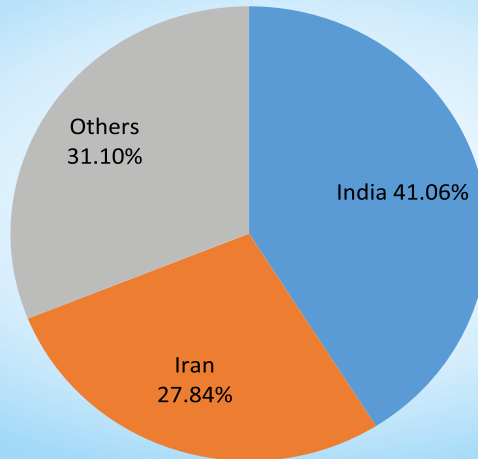
P: Provisional, Source: JPC



- India is currently the world's largest producer of Direct Reduced Iron (DRI)/ Sponge Iron in Year 2023, producing 49.33 million tonnes of Sponge Iron (as per provisional data released by world steel).



Major Sponge Iron Producing Countries in 2023



Indian Steel Sector: International Trade of Steel

- During last four years, India was a net exporter of total finished steel for each year. However, in the current financial year, April-December 2023-24, India is a net importer of finished steel as may be seen in Table below:

Table 3: Exports and Imports (000 Tonnes)					
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (Apr-Dec)
Exports	8355	10784	13494	6716	5565
Imports	6768	4752	4669	6021	4675
Net Exports	1588	6031	8824	695	-891
Source: JPC					

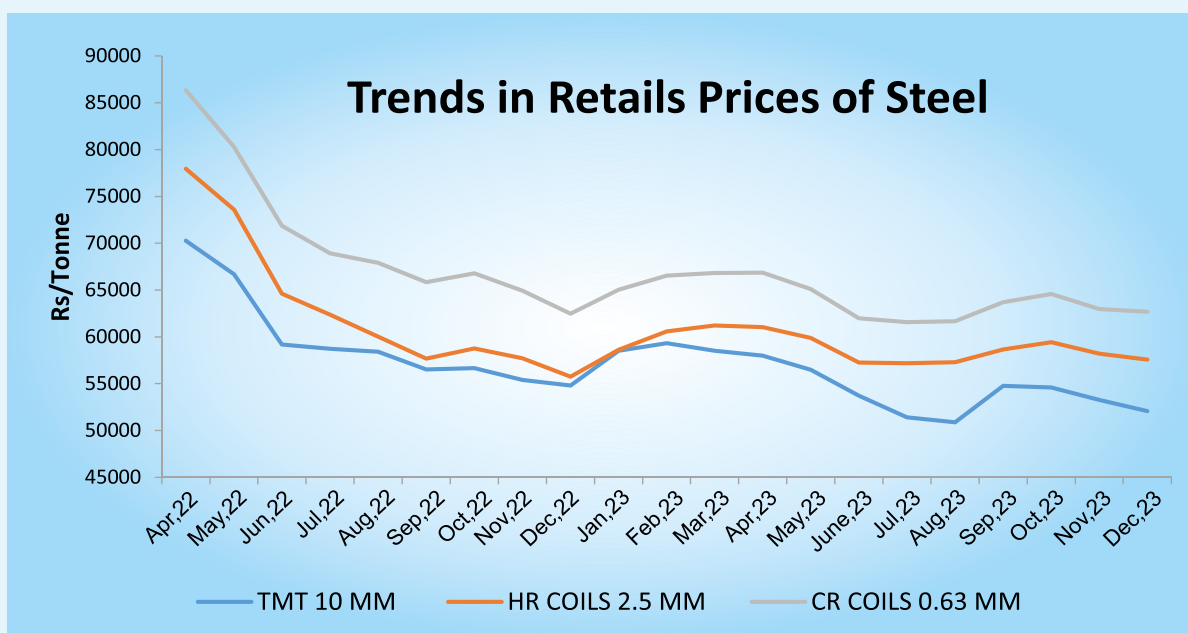
- In Q1: 2023-24, India was a net exporter of finished steel. However, month-wise data of current financial year indicates that since July, 2023 India has lost its status of net exporter as may be seen in Table and graph below:

Table 4: Month-wise Imports and Exports of Finished Steel in 000 Tonnes									
Item	Apr 23	May 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sept 23	Oct 23	Nov 23	Dec 23
Imports	460	491	484	613	728	553	730	782	725
Exports	855	693	502	513	512	430	293	234	644
Net Exports	395	202	18	-100	-216	-123	-437	-548	-82
Source: JPC									



Indian Steel Sector: Steel Prices

- Price regulation of iron & steel was abolished on 16.1.1992. Since then, domestic steel prices are determined by the interplay of market forces.
- Domestic steel prices are influenced by trends in raw material prices, demand – supply conditions in the market, international price trends among others.
- The prices of steel (TMT, HRC and CRC) peaked in March, 22 on account of Russia-Ukraine war. After that steel prices moderated till December, 22 due to both global and domestic factors. The prices of TMT, HRC and CRC have moderated in the current financial year (April-December) as is seen in the following graph:

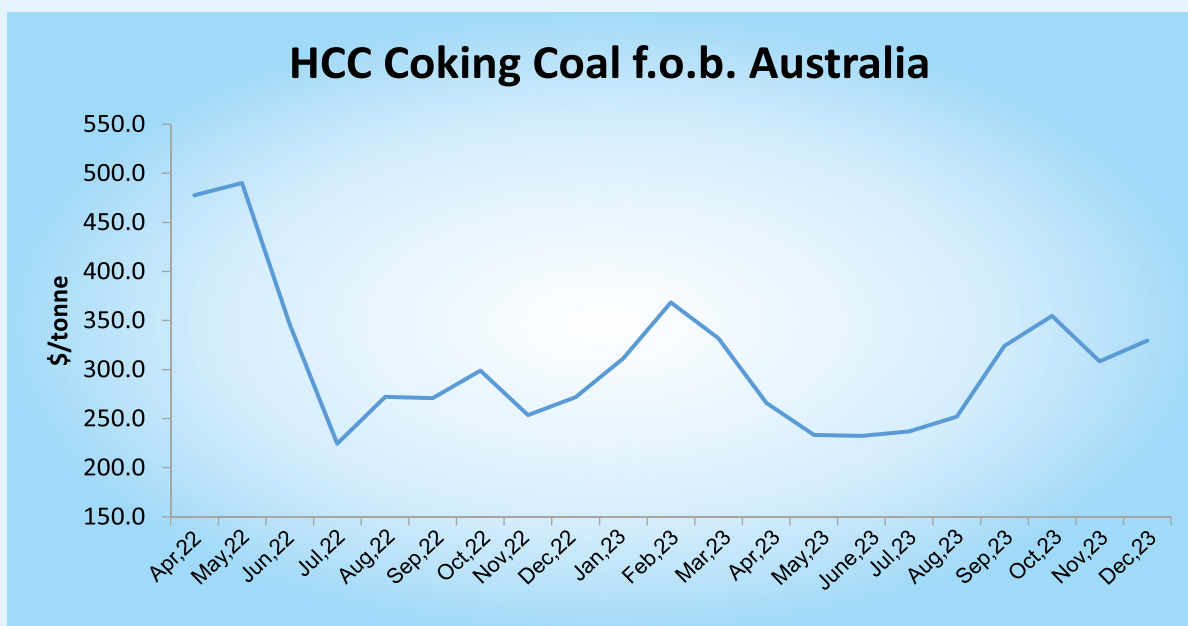




The prices of iron ore have witnessed month-on-month fluctuations since April, 2023, though there is increasing trends may be seen from the graph below:



- The prices of HCC Coking Coal FOB Australia after its historical peak in May, 22 have decreased after June, 22. During the current financial year 2023-24, prices of HCC Coking Coal have witnessed fluctuations, as may be seen from the graph below:



2.0 HIGHLIGHTS OF MAJOR INITIATIVES OF THE MINISTRY DURING 2023

PLI Scheme for Specialty Steel

In July, 2021, Government had approved the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Specialty Steel with a 5-year financial outlay of 6322 Crore to promote the manufacturing of 'Specialty Steel' within the country by attracting capital investment, generate employment and promote technology up-gradation in the steel sector. The Scheme was notified on 29.7.2021

and detailed Scheme Guidelines were published on 20.10.2021. The Scheme commences from FY 2023-24 (PLI to be released in FY 2024- 25).

On 17.03.2023, Ministry of Steel signed Memorandum of Understanding (MOU) with the 27 selected companies having 57 applications. This Scheme will attract total investment commitment of 29,530 Crore with capacity addition of 24780 thousand tonne.

Green Decarbonization of Steel Making

The steel sector plays a vital role in India's economy, contributing significantly to employment generation, infrastructure development, and industrial growth. The steel sector is a significant contributor to global greenhouse gas (GHG) emissions, with the production of steel being a carbon-intensive process. As the world seeks to combat climate change, reducing emissions from the steel industry has become a key priority. India, as one of the world's largest steel producers, faces a unique challenge in decarbonizing its steel sector while meeting the growing demand for steel. However, in-line with India's commitments towards Net-zero, as enunciated in COP-26, the Ministry of Steel has taken various steps towards decarbonization of steel sector.

Ministry of Steel constituted 14 Task Forces with the engagement of industry, academia, think tanks, S&T bodies, different Ministries and other stakeholders to discuss, deliberate and recommend upon different levers of decarbonization of steel sector. Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has announced a National Green Hydrogen Mission for boosting green hydrogen production and promoting usage. The steel sector has also been made a stakeholder in the Mission. The steel sector has adopted the Best Available Technologies (BAT) available globally, in the modernization & expansions projects.

R&D through Government Budget

Ministry of Steel seeks R&D Project proposals in joint collaborative mode from reputed Academic Institutions, Research Laboratories and Steel Companies for pursuing R&D projects for development of new alternate processes & technologies to address the burning issues faced by the Iron & Steel Sector such as climate change (green steel production, H2 based steel production, CCUS etc.), waste utilization, resource efficiency, etc. for providing financial assistance under the R&D Scheme "Promotion of Research & Development in Iron & Steel Sector".

Industrial participation, both in terms of collaboration and financial contribution, is mandatory for the R&D proposals to be considered for funding under the R&D Scheme.

During the FY 2023, a total of 4 R&D projects have been approved with total cost of Rs 360.48 lakhs with financial assistance of Rs. 239.63 lakhs from the Government budget. Additionally, there are currently 14 ongoing R&D projects of Ministry of Steel.

Steel and Steel products (Quality Control) Order

Ministry of Steel has introduced Steel Quality Control Order thereby banning sub-standard/ defective steel products both from domestic & imports to ensure the availability of quality steel to the industry, users and public at large.



As per the Order, it is ensured that only quality steel conforming to the relevant BIS standards are made available to the end users.

As on date 145 Indian Standards have been notified under the Quality Control Order covering carbon steel, alloy steel and stainless steel. In addition, goods & articles made up of steel such as stainless steel pipe & tubes, laminations/ cores of transformers, products of tin plate & tin free steel etc. have also been notified to prevent circumvention of the Steel Quality Control Order.

Safety in the Iron & Steel Sector: Formulation of Safety Guidelines for Iron & Steel Sector

Safety is an important aspect in functioning of any industry. It is important not only for its employees and workers but also for the environment and the nation. Iron and Steel production being a complex and hazardous activity, needs to take concerted efforts to prevent injuries and accidents, provide a healthy working environment.

After extensive consultations with stakeholders, academia etc., a set of 25 common minimum Safety Guidelines for the Iron & Steel Sector was formulated. These Safety Guidelines are at par with the global standards and are compliant with the requirements of the ILO Code of practice on safety in the Iron & Steel industry. Inputs have also been taken from the World Steel Association's guidance document on "Safety & Health Principles and Definitions". These guidelines have been uploaded in Ministry of Steel's website. These guidelines in the form of a book viz. "Safety Guidelines for the Iron & Steel Sector", was unveiled by the Hon'ble Steel Minister on 17th February, 2020.

The stakeholders from the Indian Steel Industry and its associations have been urged to adopt these guidelines wholeheartedly, to ensure a safe working environment for the workforce.

Ministry of Labour & Employment has been requested to facilitate mandatory adoption of the Safety Guidelines by the Iron & Steel Industry. Ministry of Labour & Employment has informed that it is under consideration of the Expert Committee set up for framing standards under Section 18 of the Occupation Safety Health & Working Conditions (OSH&WC) Code 2020.

NATIONAL METALLURGIST AWARDS

The National Metallurgist Award 2022 is a prestigious award given by the Ministry of Steel, Government of India, to recognize the outstanding contributions of metallurgists in the iron and steel sector. The award is given in five categories: Lifetime Achievement, National Metallurgist, Young Metallurgist (Environment), Young Metallurgist (Metal Science), and R&D in Iron & Steel Sector. The award ceremony was held on November 22, 2023, and the winners were:

- Dr. Kamachi Mudali Uthandi - Lifetime Achievement Award
- Dr. Debashish Bhattacharjee - National Metallurgist Award
- Dr. Rameshwar Sah - R&D in Iron & Steel Sector
- Dr. Niloy Kundu - Young Metallurgist (Environment) Award
- Agilan Muthumanickam - Young Metallurgist (Metal Science) Award

The award aims to encourage research and innovation in the field of metallurgy, especially in the areas of reducing carbon emission, increasing productivity, and using green hydrogen as a future energy source. The award also supports the vision of Aatmnirbhar Bharat, or self-reliant India, by promoting the growth and development of the domestic steel industry.

Ministry of Steel's Engagement with PM Gati Shakti National Master Plan

The Ministry of Steel has integrated BISAG-N's capabilities into the PM Gati Shakti National Master Plan, uploading geolocations of more than 2000 steel units to gain insights into steel production facilities. This information will aid in planning railway line extension, inland waterways, highways, ports, and gas pipeline connectivity. The Ministry has also mapped data of iron ore, manganese ore mines and Iron Ore Slurry Pipelines, allowing for better visibility and management of critical raw material sources. The Ministry has identified 22 key infrastructure deficiencies that need to be addressed in collaboration with other ministries for comprehensive and integrated infrastructure development. In addition, the Ministry of Steel has on boarded its CPSEs on PM Gati Shakti-National Master Plan.

The Ministry of Steel has been mandated to create Sectoral Plans for Efficient Logistics (SPEL) in line with the National Logistics Policy of 2022. The SPEL was developed using a comprehensive methodology, incorporating insights from various sources, including the Inland Waterways Plan, National Railway Plan, Draft National Logistics Plan, and stakeholder input. It aimed to understand the unique requirements and concerns of critical steel clusters like Jalna and Raipur. The initial draft Sectoral Plan for Efficient logistics plan (SPEL) was circulated among major steel producers and associations and make it available in public domain, ensuring a well-informed strategy. The suggestions received from stakeholders are being examined, and the finalized SPEL will be submitted to EGOS through DPIIT.

Steel Scrap Recycling Policy

The Steel Scrap Recycling Policy (SSRP) has been notified in 2019. It provides a framework to facilitate and promote establishment of metal scrapping centers in the country for scientific processing and recycling of ferrous scrap generated from various sources including end of life vehicles (ELVs). SSRP works out a model for collection, dismantling and shredding activities in an organized, safe and environmentally sound manner in order to cut pollution and prevent health hazards. The responsibilities of dismantling centre and scrap processing centre, roles of aggregators and responsibilities of the government, manufacturer and owner are enumerated. The shredded scrap produced by recycling would be used as raw material for steel making. This will help reduce import dependency of scrap for steel making and also likely to reduce cost of production of steel. Towards this end, MSTC Limited, a CPSE under Ministry of Steel, in Joint Venture (JV) with Mahindra Accelo, has set up Mahindra MSTC Recycling Private Limited (MMRPL). Till date, the JV has established eight (8) Vehicle Scrapping Centres at Greater NOIDA (NCR), Chennai, Pune, Indore, Ahmadabad, Hyderabad, Guwahati and Bengaluru. MSTC has also been entrusted to auction Government vehicles older than 15 years on the portal developed by the Company. The Ministry is working with the States for accelerating the ELV scrapping initiatives.



CAPEX by CPSEs under Ministry of Steel

The importance of capital expenditure in building steel infrastructure to spur high and sustainable growth in India cannot be over emphasized. The Steel CPSEs are using their own internal and extra budgetary resources (IEBR) to meet their CAPEX requirements.

During FY 2022-23, Steel CPSEs had a target of Rs. 11,590.46 crores (RE) against which the CPSEs achieved a CAPEX of Rs. 10,525.84 crores. The CAPEX in FY 2022-23 was the highest achieved by Steel CPSEs in the past five years.

The CAPEX target for FY 2023-24 is Rs. 10,300.85 crores (BE). Against this BE target, Steel CPSEs have achieved a CAPEX of Rs 6290.66 crores till December, 2023 (61.1%). The CAPEX progress is being monitored regularly and the CPSEs have been advised to ensure timely completion of projects and to achieve the physical and financial milestones.

Training & Skill Development activities undertaken by CPSEs during year 2023-24 (upto Dec 23)

During year 2023-24 (upto Dec, 23), 5091 candidates have undergone apprenticeship training through CPSEs. Further, as part of Recognition of Prior Learning (RPL) training, CPSEs have conducted training for 1357 own employees, 4460 contract workers and 366 local youth.

Statement showing implementation of provisions of Apprenticeship Act, 1961 in CPSEs under the Ministry of Steel:-

PSU	Candidates undergoing apprenticeship Training in FY 2023-24 (upto Dec,23)		Recognition of prior Learning (RPL) training (FY 2023-24 upto Dec, 23)		
	Slots Provided by RDAT/BOAT	No. of Candidates Trained in 2023	Own employees	Contract Workers	Local Youth
KIOCL	185	132	492	1979	366
MECON	33	33	145	-	-
MOIL (upto Nov' 23)	430	330	373	-	-
RINL	1019	1019	-	-	-
SAIL	4239	2989	84	2481	-
MSTC	-	14	263	-	-
NMDC	618	574*	-	-	-
TOTAL	6524	5091	1357	4460	366

* NMDC Ltd. has signed an MoU with NSDC for conducting Recognition Prior Learning (RPL) training for a total of 1600 employees over a period of four years. 50% of total amount is paid to NSDC and NSDC jointly have already identified a training partners to deliver the RPL training. Job roles furnished to NSDC. The training will commence shortly across all the projects.

3.0 MAJOR EXPANSION/PROJECTS/JOINT VENTURES BY CPSEs

Steel Authority of India Limited (SAIL)

A number of Addition, Modification, Replacement Schemes (AMR) schemes costing around

Rs 5,100 crore were under implementation during Financial Year 2022-23 in different Plants of SAIL, of which major schemes are as under:

- Setting up of Static Facility for Environmentally Sound Management of Polychlorinated Biphenyls, Installation of Electrostatic Precipitators as replacement of Multi-cyclones for Sinter Plant-II and Rebuilding of Coke Oven Battery No.7 & 8 at Bhilai Steel Plant,
- Installation of 4th Stove in Blast Furnace No. 4, Installation of NDT Facilities at Wheel & Axle Plant, Power Augmentation Scheme for new 1250 TPD BOO Oxygen Plant and Installation of New Gas Fired Boiler at Durgapur Steel Plant.
- Power evacuation at 220 KV from NSPCL to MSDSIV, Re-building of Coke Oven Battery No. 2 along with augmentation of Coke Handling & Gas Handling Facility, Up-gradation of Effluent Treatment Plant of CO & CCD with ZLD concept, Installation of 4th Slab Caster along with Ladle Furnace at SMS-II and Installation of Treatment System-1 for Implementation of ZLD at Rourkela Steel Plant.
- New Sinter Plant, Rebuilding of Coke Oven Battery No. 8, Development of alternate system for drawl of raw water from Damodar River for BSL & Township, Replacement of existing RRI (Route Relay Interlocking) System by SSI (Solid State Interlocking) System at SWS (Steel Works Station), Power supply arrangement for proposed 2000 TPD Oxygen, Installation of 2000 TPD Oxygen Plant on BOO Basis, Up-gradation of Automation System of HSM, Installation of 22 kV, 3rd line between CTPS of DVC to MRS and Replacement of Turbine & Auxiliaries for Turbo Blower No.5 at Bokaro Steel Plant.

Out of the above, following projects worth about Rs. 500 crore have been completed during the year 2022-23:

- Setting up of Static facility for Environmentally Sound Management of Polychlorinated Biphenyls at BSP.
- Installation of Electrostatic Precipitators as replacement of Multi-cyclones for Sinter Plant-II at BSP.
- Power evacuation at 220kV from NSPCL to MSDS-IV at RSP.
- Up-gradation of Effluent Treatment Plant of CO & CCD with ZLD concept at RSP.
- Rebuilding of Coke Oven Battery-8 at BSL.

Further, major Addition, Modification, Replacement Schemes (AMR) (costing Rs.150 Crore & above) projects going to be undertaken/implemented in the Plants of Steel Authority of India Limited namely Bhilai Steel Plant, Durgapur Steel Plant, Bokaro Steel Plant towards which orders have been placed during the calendar year 2023 are as under :

- Replacement of Converter vessels, trunnion rings, support system and Installation of secondary emission control system for three converters in SMS-II at Bhilai Steel Plant
- Revamping of Old Sub-Systems of Blast Furnace-3 at Bokaro Steel Plant



- Rebuilding of Coke Oven Battery No. 6 at Bokaro Steel Plant
- Rebuilding of Coke Oven Battery -4 (COB-4) at Durgapur Steel Plant

Apart from the above, orders have also been placed for the following projects on BOO / MDO/ COM basis:

- Installation of 1000tpd Oxygen Plant on COM Basis at Rourkela Steel Plant
- Engagement of MDO at Tasra Mines
- Installation of 1250 tpd Oxygen Plant on BOO basis at Durgapur Steel Plant

Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL)

1. Air Separation Plant- BOO

- Plant-1 & Plant-2 commissioned in Jun, 23, paving the way for restart and operation of Blast Furnace-3 at full capacity. PG Test-1 completed in Dec, 23. At present, both Plants are operational.

2. RINL Forged Wheel plant

- Forged Wheel Plant at Lalgunj, UP with a production capacity of one lakh wheels per annum, to cater to the requirement of Indian Railways for import substitution.
- Preliminary Acceptance Certificate (PAC) issued on 31.03.2023 after successful completion.
- Ramp up of production is improved gradually and dispatched wheels to Railways from a level of - 1039 Wheels in Apr, 23 to 3128 Wheels in Dec, 23.
- Total number of 17721 Wheels (LHB + LOCO) dispatched to Indian Railways in current year till Dec,23.

NMDC Limited:

Setting up NMDC Steel Limited (NSL):

- NMDC Steel Limited is a public company incorporated on January 2, 2015 under the Companies Act, 2013 having its registered office at C/O NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, Bastar, Chhattisgarh.
- This 3 MTPA capacity Greenfield integrated steel plant has been set up at Nagarnar, located 16 km from Jagdalpur in Chhattisgarh state. The decision to construct the NISP was taken keeping in view the linkage with iron ore reserves and availability of investable surplus.
- The plant was become functional on August 24, 2023 when first Coil was rolled out. First HR coil rolled out on 24.08.2023. The project cost is Rs 23840 crore. NMDC Steel Ltd. (NSL) was dedicated to Nation by Hon'ble PM on 3rd October, 2023.

- As on 31.12.2023, NSL has produced about 5.33 lakh tonnes of Hot metal from Blast Furnace, 2.10 lakh tonnes of Liquid Steel, 1.95 lakh tonnes of HR coils.

Other Greenfield & Brownfield projects of NMDC

1. 3.0 MTPA Integrated Steel Plant at Nagarnar, Chhattisgarh

- Capacity- 3.0 MTPA.
- Project Cost: ₹ 23840 Cr.
- Blast Furnace operation commenced on 12.08.2023 and hot metal production done on 15.08.2023.
- SMS operation commenced on 21.08.2023.
- TSC-HSM operation commenced on 24.08.2023 and first HR coil rolled out on 24.08.2023.
- The NMDC Steel Plant at Nagarnar was dedicated to Nation by the Hon'ble Prime Minister of India on 03.09.2023.

2. Slurry Pipeline Project Phase-1 at Chhattisgarh

- NMDC has taken up construction of Slurry Pipeline project which consists of 2.0 MTPA Pellet Plant at Nagarnar, 2.0 MTPA Ore Processing Plant at Bacheli and 135 Km Slurry Pipeline from Bacheli to Nagarnar and its Auxiliary systems in the state of Chhattisgarh. All packages like Slurry pipeline laying package, Slurry Pump house package, Technological package of Pellet Plant at Nagarnar, Main Substation Packages and Technological Package of Ore Processing Plant at Bacheli are awarded and works are in progress at site. All statutory clearances are obtained.
- Project Cost: ₹ 2907 Cr.
- Overall progress of the project: 55.10%
- 49 km Cumulative lowering of Water Pipeline & Slurry Pipeline completed.

3. Screening Plant-III, Kirandul, Chhattisgarh

- NMDC has taken up Installation of 12.0 MTPA Screening Plant -III at Kirandul Complex, Bailadila, Chhattisgarh. All statutory clearances are obtained. Major packages like Dry Circuit Package, Wet Circuit Package, RWLS Package, Main Substation Package are awarded and work is in progress at site.
- Project Cost: ₹ 2719 Cr.
- Overall progress of the project: 48.46%

4. Construction of 5th Screening line in existing Screening Plant and Up-gradation of downhill conveyor system at deposit-5, Bacheli Complex, Bailadila, Chhattisgarh

- Project Cost: ₹ 67 Cr.



- Overall progress of the project : 90%.
 - 5th Screening line in Screening Plant is completed and taken in to operation.
5. **Installation of 7.0 MTPA Screening & Beneficiation Plant-II at Donimalai Complex, Karnataka.**
- Project Cost: Rs. 1044 Cr.
 - Expected Completion: March, 26.
 - Statutory Clearances like Forest Clearance & Environment Clearance are obtained.
 - Tendering activities in progress.
6. **New crushing Plant and Downhill conveyor system at Deposit 14 & 11C**
- Project Cost: ₹ 1756 Cr.
 - Environment Clearance in progress.
 - Tendering activities in progress.
 - Completion period: 36 months for execution after awarding of packages (Linked with Environment clearances).
7. **Doubling of Kirandul - Kottavalasa line from Kirandul to Jagdalpur (150 km approx.)**
- Project is being executed by East Coast Railways on deposit basis, funded by NMDC. Total 106 km out of 150 km doubling from Jagdalpur to Dantewada is commissioned and opened for traffic. Out of sanctioned ₹ 1500 Cr. fund (maximum), NMDC released ₹ 1363 Cr. so far and balance ₹ 137 Cr. shall be released in phases based on the work progress.
8. **NMDC's Solar Projects: Rooftop Solar Plant at Bacheli Complex, Chhattisgarh**
- Capacity: 425 kWp Rooftop Solar Power Plant.
 - Project Cost: ₹ 3.36 Cr. including O&M for 10 years.
 - Project commissioned on 14.03.2023.

MOIL Limited

1. MoU with Chhattisgarh Mineral Development Corporation (CMDC):

A MoU was signed between MOIL and CMDC on 16th January, 2023. Further to this, CMDC applied for reservation of a suitable block under Rule 67 of MCR 2016 for exploration to Govt. of Chhattisgarh. The Govt. of Chhattisgarh allotted 218 sq. km. area in the Balrampur District for exploration on dated 04.10.2023. MOIL will start exploration work in this area soon.

2. MoU with TEXMiN:

Government of India has established "technology innovation hub for mining and

exploration” under the national mission for inter-disciplinary cyber-physical stem (NMICPS) under Department of Science and Technology at Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad which, is known as TEXMiN. MOIL Limited and TEXMiN entered into a MoU on dated 17.12.2023 to work together as collaborative Research Team for Technological Development in the fields of Mineral Exploration, Mechanization, Digitization etc. in mining projects.

MECON Limited

1. **Signing of MoU:** MECON, as Project Management Agency to Ministry of Steel (MoS), is implementing Ministry's flagship Production Linked Incentive (PLI) Scheme. Under the Scheme, expected capacity creation of 25 MTPA with investment of ₹ 30,000 Crores is a step forward in achieving the vision of AtmaNirbhar Bharat in Specialty Steel. For this scheme 27 companies signed 57 MoUs with MoS with total investment of INR 10730 Crores.
2. **Longest HDD crossing:** MECON is providing PMC services for execution of Hon'ble Prime Minister's visionary project of Urja Ganga which aims to provide piped cooking gas to Households in the different states through cross country pipelines. MECON has completed more than 4800 km length of pipeline across 24 states and 5000 km of pipeline projects are under execution.

The North East Gas Grid Project (NEGG) of IGGL at Guwahati is part of this prestigious project wherein MECON has completed Nation's Longest Horizontal Directional Drilling(HDD) crossing of 4080 metres in April 2023 (from Jorhat to Majuli in Assam) at Brahmaputra River while rendering Project Management & Consultancy (PMC) services for the Project (NEGG).

MECON is the only indigenous Design, Engineering & PMC Organisation, with experience of executing long (~ 4000 m) river crossings by HDD.

3. **Projects of Floating Jetty and Conversion Diesel/Petrol boats to CNG:** MECON is entrusted by M/s GAIL with Engineering and Project Management Consultancy (EPMC) Services for CNG Dispensing Station on first-of-its-kind Floating Jetty (on Mild Steel Modular Jetty) on river Ganga at Khirkiyaghat (now known as NaMoghat) and conversion of more than 700 nos. of Diesel/Petrol boats to CNG. These projects were inaugurated by Hon'ble Prime Minister of India at Varanasi. This station has been awarded with best innovation in Oil & Gas Sector at Kuala Lumpur, Malaysia.

Under this project the world's first floating CNG Daughter Booster Station (DBS) on the basis of Mobile Refuelling Unit (MRU) concept was installed at the other end of river Ganga ferry line at Sant Ravidas Ghat and inaugurated by Hon'ble Minister MoPNG.

These projects are a step towards Gas based economy and are expected to reduce pollution, and save marine life.

4. **Commissioning of Blast Furnace:** MECON provides complete know-how and technology, from concept to commissioning of BF complexes and is the only indigenous company having its



own Blast Furnace design which has been installed in 23 Mini Steel Plants across the country and is accounting to 7 to 8 MT in secondary steel sector.

MECON commissioned its own designed 0.4 MTPA Blast Furnace at Bengal Energy, Kharagpur, West Bengal. Blast Furnace is equipped with all modern features like Staves, Bell Less Top (BLT), Pulverized Coal Injection (PCI), Filter bed Slag Granulation Plant (SGP), etc.

5. **Commissioning of COB#8, Bokaro Steel Plant:** MECON provides complete know-how and technology, from concept to commissioning of Coke Oven Batteries and is the only indigenous company having its own 7M tall Coke Oven Battery design.

COB#8, BSL is the 33rd Battery commissioned by MECON. COB#8 has consistently met operational parameters, achieving 94-96 pushing (out of maximum rated 100 number of pushing) within just 2-3 months from its date of commissioning. The number of pushings can be further increased up to 100 whenever needed to cater to production parameters. In terms of pollution, its performance is with almost zero leakages.

COB#8 was commissioned with the repair of the existing concrete nozzle deck using the Fiber-Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) methodology (used for the first time in India in any Coke Oven battery).

6. **Inauguration of Rare Earth Permanent Magnet Plant:** Hon'ble Prime Minister inaugurated and dedicated the Rare Earth Permanent Magnet Plant in Visakhapatnam to the nation. The plant will produce rare earth magnets like samarium-cobalt and neodymium-iron-boron. With this facility, India will join a select group of nations with capacity to produce rare earth permanent magnets.

MECON was involved in Designing, Engineering, Supervision, Erection & Commissioning activities of the Plant at Vishakhapatnam.

7. **Commissioning of NSL:** NMDC Steel Limited (NSL) has been designed with mega modules technological facilities which includes one of the largest Blast Furnace in India with a capacity 4506 m³ (Useful Volume), Hot Strip Mill coupled with Thin Slab Caster (TSC), Basic Oxygen Furnace (BOF), and two 7 m tall Coke Ovens.

MECON is providing Consultancy and Project Monitoring & Construction Supervision & O&M Services for the 3 MTPA Integrated Steel Plant of NMDC Steel Limited (NSL)

8. **Award of Patent:**

MECON has been awarded a total of 50 patents. The recent being:

- Patent for invention of new design of "Basic Oxygen Furnace Vessel Suspension System."
- A patent has been granted to MECON for an invention of 'Continuous Multi Component Gas Analyzer using Non-Dispersive Infra-Red (NDIR) Method'. The developed system is useful for the measurement of concentration of Gaseous Pollutants CO, CO₂, NO_x (NO, NO₂), SO₂.

9. **Roof top Solar Power Plant:** Under Renewable Energy Development projects, MECON has committed to set up 140 kWp Rooftop Solar Photovoltaic Power Plant in 4 phases at MECON Head Office, Ranchi. Solar plant with capacity 80kWp is already installed in 3 phases and running successfully.

In March, 22, a 60 kWp roof top Solar Power Plant has been installed in 4th Phase, with this the total solar installed capacity at MECON Head Office is now 140 kWp. The solar plant is connected with Grid and it will generate around 80,000 kWh energy yearly.

KIOCL Limited

1. Development and Commencement of Mining Operation at Devadari Mines

Govt. of Karnataka issued Gazette notification dated 23.01.2017 for reservation of 470.40 ha Iron Ore Block in Devadari Range, Sandur Taluk, Ballari District in favour of KIOCL for mining of iron and Manganese ore, under Section 17A (2) of MMDR Act, 1957. KIOCL executed mining lease deed of Devadari Iron Ore Mine with Director, Mines and Geology, Govt. of Karnataka on 02.01.2023 for 388 ha area for a period of 50 years for Iron Ore & Manganese Ore (ML No. 020 of 2023) and also registered the Mining Lease Deed of Devadari Iron Ore Mine on 18.01.2023 at the Office of Sub-Registrar, Sandur Taluk, Ballari Dist.

Govt. of Karnataka issued Government Order on 11.04.2023 for diversion of forest land. DCF Ballari vide mail dated 03.01.2024 shared draft forest lease agreement for execution of agreement.

MECON submitted Modified Mine Plan on 31.08.2023. The Mine plan got approved by IBM officials on 11.10.2023.

KIOCL has planned to start mining Iron Ore by October, 2024 from Devadari Iron Ore Mine.

2. Installation of Vertical Pressure Filters at Pellet Plant Unit, KIOCL Limited, Mangaluru

The existing vacuum disc filters at Pellet Plant are not able to handle Iron ore having high Alumina content and slimy in nature. 04 Nos. of Vertical Pressure Filters, all auxiliary equipments including conveyor system, Electrical & Instrumentation equipments are installed. M/s METSO, Sweden Engineers are working at site for commissioning of pressure filters. The integrated commissioning of one line of pressure filter is completed successfully with discharge of cake for Pellet feed.

3. Installation and Commissioning of Coke Oven Plant (Backward integration project of existing Blast Furnace)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India vide letter dated 27.02.2020, had accorded Environmental Clearance for setting up of Non-Recovery Coke Oven Plant (0.18 MTPA) with Cogen Captive Power Plant (10MW) and Ductile Iron Spun Pipe (DISP) (0.2 MTPA) within the existing premises of Blast Furnace Unit at Mangaluru. KIOCL has floated Global Tenders and Domestic Tenders for the main packages. Coke Oven Plant is under construction and expected to be commissioned by 30.06.2024.



4. Modernization & Upgradation Projects at KIOCL Limited, Mangaluru

a) Construction of Coke Shed and Mechanized Material Handling system at Pellet Plant Unit

Total 180 Nos. of RCC piles and pile caps are completed till now. Construction of RCC retaining walls approx. 80% is completed & Structural fabrication jobs & erection of columns are under progress. The project completion schedule for piling and civil works, fabrication and erection of the steel structures is expected to be completed by 31st April, 2024. Tenders are floated for procurement of conveyors, weigh feeder, erection of equipment and power distribution system, which are tender evaluation. The Mechanized Material Handling system at PPU would be completed by 31.12.2024 as per the schedule.

b) Installation of LNG Dual fire burner system for indurating machine of Pellet Plant

The work order was placed on M/s EIL for detailed engineering and based on the report submitted by M/s EIL Limited, tender was floated on 02.09.2023 for supply of burner management system. The tender was opened on 14.12.2023. The sole bid received against the tender is under technical evaluation. The price bid of sole bid will be opened if the agency is techno-commercially qualified to know the market price. As more CAPEX has been already incurred on Devadari Iron Ore Mine Project, the implementation of LNG dual burner system project will be taken up in the FY 2024-25.

4.0 HIGHLIGHTS OF CPSEs DURING 2023

Steel Authority of India Limited (SAIL)

1. Production Performance during FY 2022-23

- Highest ever annual Hot Metal Production at 19.409 MT
- Highest ever crude steel production at 18.2921 MT
- Highest ever annual saleable steel production at 17.246 MT
- Highest ever annual iron ore production at 34.15 MT

2. Production Performance during 9M FY 2023-24

Unit: '000T

PLANT/ITEMS	April-Dec, 23		% growth Over CPLY
	2023-24	2022-23	
HOT METAL	15153	14160	7
CRUDE STEEL	14223	13337	7
SAL.STEEL	13718	12547	9

3. Financial Performance during H1 FY 2023-24

* In Rs. crore

Particulars	H1 2023-24	H1 2022-23	% growth Over CPLY
Total Income	54687	51022	7.18
Profit Before Tax (PBT)	1898	523	262.90
Profit After Tax (PAT)	1390	391	255.49

4. Sales Performance and Initiatives during CY 2023

- In CY 2023 CMO Sales was 16.72 Million Ton which is growth of 5 % over CPLY.
- A total of 11.59 Lakh Tonnes of rails were supplied to Indian railways during CY 2023, the 260m long-rail welded-panel component in the total rail supply being about 86%, which is highest ever.
- One rake of Head Hardened Rails in R350 HT grade has been despatched to Indian Railways.
- SAIL supplied entire plates for Indian Navy vessels Androth, Anjadip Sanshodhak, Vindhayagiri, Mahendragiri and Amini .
- Towards digitalization, AI based Chatbot '**SAIL SARATHI**' has been introduced for facilitating easier navigation & information accessibility for customers and visitors. CMO has opened a verified business account on WhatsApp. The WhatsApp account is integrated with SAIL SARATHI APP.
- In order to expand reach to niche segments with value added products and to explore new markets SAIL is constantly coming with new grades steel like Sail Forming 410 from HSM2 at RSP, 0.35mm GSM80 GP from HDGL at BSL, HSFQ550. Certification was obtained for API grades and Hi strength LPG (IS 15914 HS345) HRC from HSM2 at RSP. Wire Rods 15B25, 10B33, 1030Cr, 19MnB4 (Modified High C) at ISP, value added Semis: SUP 11A, 51CrV4, 20MnCr5 at ISP. SAIL has successfully developed Head hardened Rails in R-350 HT grade as required by Indian Railways.

Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL)

- Blast Furnace -3 blown-in on 30.12.2023 after 701 days
- Growth over CPLY achieved in major production areas viz. Hot Metal-3.403 Mt (10%), Crude Steel- 3.22 Mt (11%), and Finished Steel -2.771 Mt (11%)
- Achieved Saleable Steel production of 3.084 Mt with 13% growth over CPLY
- Achieved Sales volume of 3.07 Mt with 21% growth over CPLY



- Achieved Sales Turnover of Rs. 16,766 Crs- growth of 8% over CPLY.
- Achieved Value Added Steel sales of 9.91 lakh tons - growth of 47% over CPLY

Initiatives in production, as a part of cost reduction and revenue maximization, include:

- Maximization of High end Value Added Steel in Saleable Steel increased to 42% in Apr-Dec 2023-24 from a level of 26% in 2022-23.
- To substitute Iron Fines, usage of Iron Ore Slime in Sinter making is improved to 25% during Apr-Dec, 23.

Initiatives for securing raw material / working capital support:

- Credit line of \$100 million could be established through a Trade Partner for imported coking coals
- MoU entered with a Customer for supply of 90,000t per month of Blooms against raw material / working capital support for Blast Furnace -3 (monthly support of Rs. 800 to 900 Crs. approx.)

GeM procurement

- Total value Rs 1922.5 Crs of procurement made in current FY till Dec,23, registered an improvement of 54.34% over CPLY.

Awards

National Energy Leader Award for the 5th time consecutively by the Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, Govt. of India as RINL awarded **Excellent Energy Efficient Unit Award** for seventh time in row from 2017 onwards, by CII Godrej Green Business Centre in recognition of efforts towards energy Conservation, energy efficiency and GHG (greenhouse gas) reduction.

NMDC Limited

Physical Performance of NMDC

Particulars	(in MT)
Production of Iron ore during the year 2023-24 (upto Dec, 23)	31.79 MT
Domestic Sales of Iron ore during the year 2023-24 (upto Dec, 23)	31.97 MT
Export Sales of Iron ore during the year 2023-24 (upto Dec, 23)	NIL
Total Sales of Iron ore during the year 2023-24 (upto Dec, 23)	31.97 MT
NMDC has earned profit before tax of Rs. 3,608 crore during the year 2023-24 (upto Sep 2023).	

Other achievements:

Skill Development

NMDC has partnered with the Govt. of Chhattisgarh in establishing “**Education City**”, an island of educational facilities in Geedam, Dantewada with institutions ranging from Primary to Professional institutes in a single campus with an objective to help local children get quality education. NMDC is continuing with the operation of the Polytechnic College located therein, with two streams i.e., Electrical & Mechanical with an intake of 126 students is being operated successfully.

NMDC continues its promotion of the cause of Technical education & skill development by supporting the operation of two Industrial Training Institutes:

- The ITI at Bhansi with 5 trades is being operated successfully with the intake of 128 students each year
- The ITI with Welder & Mason trades at Nagarnar with the intake of 28 students each year is being operated successfully.

Promotion of Sports: NMDC took up the work initiative w.r.t. construction of additional facilities in the Multipurpose Sports Complex, which is under construction at Dharwad in Karnataka. The Company is partnering with the State Authorities in the above activity, wherein NMDC’s contribution would be up to Rs.14.23 Crore.

Achievements of Material Management :

I) PROCUREMENT:

1. Procurement of Goods and Services through GeM portal value of **Rs. 880 Cr** against the Target of **Rs. 840 Cr** set by Ministry of Steel.
2. Procurement through MSE Firms **46%** as against Target of **25%** set by MoU.

II) DIGITAL INITIATIVES:

- 1) **Supplier Relationship Management (SRM)** e-Procurement Portal implemented, which would facilitate inhouse e-Tendering activities without relying on any Service Providers.
- 2) **File Lifecycle Management (FLM) (paperless office)** has been developed in our ERP module and same is in the process of implementation.
- 3) Acceptance/ Rejection of Invoices of Goods & Services of MSE firms through **TReDS** Portal.
- 4) Integration of GeM portal with SAP system.
- 5) Development of Vendor Invoice Management (VIM) Portal and integration of TReDS portal with VIM portal.



MOIL Limited

- **Production:** MOIL has recorded manganese ore production of 12.73 lakh MT upto December, 2023, registering a growth of ~ 42% over corresponding period last year (CPLY).
- **Sales:** Sales of manganese ore at 11.01 lakhs tonnes, ~ 40% higher over CPLY.
- **Electrolytic Manganese Dioxide (EMD):** Production of EMD has also increased by 30% over CPLY i.e. from 808 MT to 1051 MT.
- **Ferro Manganese (FeMn):** Production of FeMn has also increased by ~6% over CPLY i.e. from 7363 MT to 7831 MT.
- **Sales Turnover** has also increased by about ~13% over CPLY i.e. from 915.65 cr to 1034.52 cr.
- **Capex:** MOIL has achieved capital expenditure (capex) of 216.09 cr., registering a growth of 55% over CPLY.
- **Procurement through Government e-Market Place (GeM):** MOIL has achieved the highest GeM (Government e-Market place) procurement i.e. Rs. 282 cr. against the target of Rs. 175 cr.

MECON Limited

- MECON has achieved Profit before Tax of Rs. (-) 114.74 crores (prov.) in F.Y. 2023-24 (upto 31st December, 2023) and the order booking of Rs. 866.64 crores for the FY 2023-24 till 31st December, 2023.
- MECON is a debt-free CPSE, with paid-up equity share capital of Rs. 40.14 Crores and Net Worth of Rs. 336.46 crores (prov.), as on 31st December, 2023.
- The company has paid Rs. 9.30 crores as dividend to GOI for F.Y. 2022-23.

MSTC Ltd.

MSTC was able to achieve growth of around 4.13% in revenue from operations net of purchases over last year. PBT rose by around 42.46%. PAT rose by 19.56% that has resulted in highest ever profit figure for the company. During the financial year MSTC:

- Has crossed INR 3015.90 bn in terms of value of goods transacted through its marketing and e-commerce vertical, which is 120% increase over the value of goods traded in 2021-22;
- Has recorded total volume of ₹498.00 crores;
- Total ecommerce service charge has increased from ₹264.00 crores to ₹288.00 crores, which is a growth of 9%;
- Profit after Tax during the financial year was ₹239.23 crores compared to ₹200.05 crores in the previous financial year and Profit before Tax during the financial year was ₹313.48 crores

compared to ₹220.04 crore in the previous financial year riding mainly on the e-commerce contribution;

- Paid Interim Dividend of ₹11.80 per share. In addition to that board has also recommended payment of final dividend of ₹3.20 per share, which will be paid to the shareholders after shareholder's approval in the ensuing AGM;
- MSTC has launched ELV portal for disposal of 'End of life' vehicle for Central and State Govt.

KIOCL LIMITED (upto December, 2023 of FY 2023-24)

- Achieved Production of 1.501 Million Tonnes of Iron Ore Pellets.
- Achieved Sales of 1.469 Million Tonnes of Iron Ore Pellets
- Achieved a Turnover of ₹1481.98 Crores.
- From April, 2023 to December, 2023, earned foreign exchange equivalent to ₹1277.42 Crores.

(Note: Financial figures are provisional and subject to Audit.)



उत्पदन संबद्ध प्रोत्साहन योजना
(पीएलआई)
का कार्यान्वयन

16 जनवरी, 2024 को संसद
सौध विस्तार भवन में आयोजित की
गई परामर्शदात्री समिति
की बैठक



इस्पात मंत्रालय ने 22 नवम्बर, 2023 को
लौह एवं इस्पात क्षेत्रों में धातु विज्ञानियों
की उत्कृष्टता और योगदान का सम्मान
करने के लिए नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड
2022 प्रदान किया।



इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार

Ministry of Steel
Government of India

www.steel.gov.in